RNI No. 58061/93 ■ वर्ष - 21 ■ अंक - 346 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » गुरुवार » 16-07-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है : आदित्यनाथ

6 क्या भारत विरोध ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेला?

राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा होता है लोकतंत्र : उपराष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/भाषा। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने लोकतंत्र को राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा बताते हुए बुधवार को कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता और संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। वह यहां राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत 'विधान गौरव यात्रा भूतपूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन' के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पूर्व व वर्तमान सदस्यों का यह अद्वितीय समागम एक सशक्त संदेश दे रहा है कि संस्थाएं व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और लोकतंत्र राजनीतिक मतभेदों से कहीं बड़ा होता है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन कम से कम एक चीज ऐसी है जिसके प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता होनी चाहिए और वह है जनता और संविधान के प्रति हमारी निष्ठा। उन्होंने कहा, मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में अक्सर कहा करता हूं कि बहस, चर्चा और

कभी-कभी व्यवधान भी अंतत: किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने का माध्यम होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव तो जनता के वोटों से जीते जा सकते हैं लेकिन उनके दिल को जीतने के लिए उनकी सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा, चुनाव के समय हम जनता के मतों से चुनाव जीतते हैं लेकिन उनके दिलों को हम तभी जीत सकते हैं जब जी-जान से उनकी सेवा करें। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं या नहीं।

सोलहवां पुण्यस्मरण दिवस

देवलोकगमन 16.7.2010

स्व. संघवी श्री भंवरलालजी बोहरा

(सुपुत्र-स्व.श्री गुलाबचन्दजी बोहरा)

समाज सुदृढता के लिए दान प्रवृत्ति को बढावा देना, जिनमंदिरों के निर्माण में सदैव तत्पर, सब परिवारजनों के साथ स्नेहभरा सामंजस्य स्थापित कर अटूट पारिवारिक बंधन को हमेशा मजबूत करने की प्रेरणा देने वाली इस दिव्यात्मा के सद्कर्म सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। हम सबकी ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को सादर विनम्र श्रद्धांजलि।

श्रद्धावनत

धर्मपत्नी : श्रीमती पिस्ताबाई बोहरा

सुपुत्र-पुत्रवधु : संघवी इन्दरचन्द-पुष्पाबाई,
संघवी रमेशचन्द-शकुंतलाबाई, संघवी मंगलचन्द-त्रिशला बोहरा

सुपौत्र-पौत्रवधु : प्रदीप-सीमा, अरुण-ममता, महेन्द्र-अक्षिता, विकास-सीमा, करण-निकिता, राहुल-वृद्धि, पड़पौत्र-पड़पौत्रियां : हर्ष, हार्दिक, प्रणाली, विनती, मिताली, मयंक, पृथ्वी, चेहक, हुनर, माही एवं
समस्त बोहरा परिवार, (बिलावास)

पुत्री-जंवाई : लीलाबाई-गौतमचन्दजी कोचेटा, सुशीलाबाई-आनंदराजजी मेहता
पौत्री-जंवाई : प्रिया-राकेशजी, मान्या, प्रांजल, बिलवाड़िया, सुमन-करणजी, विहाना मरलेचा नीलम-भावेशजी, रियांश सोनीगरा, करुणा-आशीषजी कोचर, कीर्ति-कुणालजी गांधी

B.G. BHAWARILAL BOHRA & SONS
171, J.M. Road, (O.P.H. Rd) Cantt., Bangalore 560 051, 93412 14405

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

भले ही हों

सोनम मरे जिये या उनका,
बॉडी वीक भले ही हों।
जिम्मेदार नहीं सरकारें
पेपर लीक भले ही हों।
बहरी हैं सारी सत्ताएं,
मांगे ठीक भले ही हों।
कॉकरोच मसले जायेंगे,
नीयत नीक भले ही हों।।

वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह यहां जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताने वाली जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितताओं के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 25 दिन से अधिक समय से प्रदर्शन कर रही है। वांगचुक 28 जून को इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उच्च न्यायालय की बार

एसोसिएशन द्वारा आहूत कार्य बहिष्कार के बीच संबंधित प्राधिकारियों की ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी।

पीठ ने कहा, ''मामले की तात्कालिकता को देखते हुए इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।'' अदालत ने आदेश की एक प्रति संबंधित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सैनी ने कहा कि स्थिति ''दुखद'' एवं ''बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'' है क्योंकि प्रदर्शन कर रहा एक नागरिक पूरे देश के सामने एक तरह से अपनी जान दे रहा है। सैनी ने अपनी जनहित याचिका में अनुरोध किया है कि संबंधित प्राधिकारियों को वांगचुक की मदद करने और उनसे इस मुद्दे पर ''बातचीत करने'' का निर्देश दिया जाए।

अरुणाचल में बाढ़ की स्थिति भयावह, 26 जिलों में एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। राज्य के 28 में से 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इस आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। यह जानकारी राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) की ओर से जारी बुलेटिन में दी गई। एसईओसी के अनुसार, बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, क्रा दादी, कामले और पापुम पारे जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की नई घटनाएं दर्ज की गईं।

अपर सुबनसिरी जिले में लाइमकिंग, नाचो, सियुम और दापोरिजो सर्किल बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए। अपर सियांग जिले के मरियांग, यिंगकियोंग, पल्लिंग और जेंगिंग सर्किलों में भी क्षति की सूचना मिली।

॥ श्री वरकाणा पार्श्वनाथाय नमः ॥
॥ श्रीमद् आत्म वल्लभ समुद्र इन्द्रदिन्न नित्यानंद सद्गुरुभ्यो नमः ॥

धर्मनगरी बेंगलुरु की धन्य धरा पर

गोडवाड वल्लभ चातुर्मास आयोजक समिति के तत्वावधान में

पंजाब केसरी परम पू.पू. आचार्य भगवंत श्रीमद् विजय वल्लभसूरीश्वरजी म.सा. के समुदाय के

वर्तमान गच्छाधिपति, भारत सरकार द्वारा "पद्मश्री" से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित, कल्याणक तीर्थोद्धारक,

शांतिदूत श्रीमद् विजय नित्यानंद सूरीश्वरजी म.सा.

विश्व शांति प्रदायक महामंगलकारी भव्यतम-दिव्यतम संक्रान्ति समारोह

आषाढ सुदि 3, दि. 17 जुलाई 2026, शुक्रवार

* पंन्यास प्रवर श्री धर्मशील विजयजी म.सा. * मुनिराज श्री मोक्षानंद विजयजी म.सा. * मुनिराज श्री धरणेन्द्र विजयजी म.सा.
* मुनिराज श्री ज्ञानानंद विजयजी म.सा. * तपस्वी मुनिराज परमानंद विजयजी म.सा. आदि ठाणा
* साध्वी सिद्ध प्रज्ञा श्रीजी म.सा. * साध्वी रश्मि प्रज्ञा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा

आत्मिक - आमंत्रण

मंगलमय कार्यक्रम

प्रभु भक्ति, गुरु कृपा, दान और अनेकविध धार्मिक अनुष्ठानों को समर्पित संक्रान्ति महोत्सव

पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत का भव्य सामैय्या - प्रातः 8.30 बजे
(मेघा रेसीडेंसी, वाणी विलास रोड क्रॉस, बसवनगुडी, बेंगलुरु-04 से)

महामांगलिक संक्रान्ति समारोह - प्रात: 10.00 बजे

स्थल : श्री महावीर धर्मशाला, वी.वी.पुरम, बेंगलुरु

साधर्मिक भक्ति : 12.15 बजे से

लाभार्थी परिवार

दिव्य आशीष - स्व. चैनराजजी स्व. सिरेकंवरदेवी
शिखरचंदजी, हुक्मीचंदजी, विमलचंदजी, नरेशकुमार, संजयकुमार, विरेन्द्रकुमार, निखिलकुमार, सिद्धार्थकुमार
एवं समस्त गाँग परिवार बेंगलुरु (मरुधर में रुण-नागौर)

Sankeshwar Developers
Green Arihanth Agro

गच्छाधिपति का गुरु कृपा चातुर्मासिक महाप्रवेशोत्सव 19 जुलाई 2026, रविवार
(श्री गोडवाड भवन, लाल बाग रोड क्रॉस, बेंगलुरु)

चेयरमैन

दिलीप घेवरचन्दजी सुराणा | भंवरलाल हस्तीमलजी रांका | विक्रम भीमराजजी करबावाला

निवेदक : गोडवाड वल्लभ चातुर्मास आयोजक समिति 2026, बेंगलुरु • संपर्क सूत्र : 98454 12014

वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव, राहत कार्य प्रभावी ढंग से किया गया : सतीशन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद राज्य सरकार ने बचाव, राहत एवं पुनर्वास का काम प्रभावी ढंग से किया। उन्होंने मंत्रियों और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों की भी सराहना की। सतीशन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि आपदा के बाद सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी काम प्रभावी ढंग से पूरे किए गए। उन्होंने वायनाड भूस्खलन के बाद वहां किए गए कार्यों के लिए राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार और कृषि मंत्री टी सिद्दीक की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई आपदाओं में कुछ समय बाद तलाश अभियान बंद कर दिया जाता था लेकिन वायनाड में सभी आठ शव बरामद होने तक अधिकारियों ने अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के दौरान जान गंवाने वाले राज्य के बाहर के लोगों के परिजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सतीशन ने कहा कि सरकार ने विशेष विमान की व्यवस्था सहित शवों को उनके पैतृक स्थानों तक ले जाने का भी इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास का काम शुरू कर दिया गया है और चिन्हित खतरे वाले इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों ने कोंकण रेलवे और उसकी सहयोगी कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने संबंधित कंपनी के साथ समझौता भी किया है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से घोषित मुआवजे के अलावा कंपनी पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देगी।

मंदिर जाना मेरा निजी अधिकार है, 'उदार हिंदुत्व' नहीं : केरल के मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने कोल्लूर मूकांबिका मंदिर की अपनी हालिया यात्रा को लेकर लगाए गए 'उदार (सॉफ्ट) हिंदुत्व' के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि उनकी आस्था उनका निजी मामला है, जिसे संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त है। सतीशन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि वह पिछले 37 वर्षों से कर्नाटक स्थित इस मंदिर में (पूजा-अर्चना के लिए) जा रहे हैं तथा केवल इस आधार पर उन्हें उदार हिंदुत्व'' का नेता बताना पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने कहा, ''मूकांबिका मंदिर जाना मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। मुझे भगवान में आस्था रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसे 'उदार हिंदुत्व' कैसे कहा जा सकता है?'' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1990 के दशक से इस मंदिर में जाते रहे हैं। उन्होंने खुद को वहां की अधिष्ठात्री देवी का भक्त बताया। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले 37 वर्षों से मूकांबिका मंदिर जा रहा हूं। मैं कोल्लूर मूकांबिका का भक्त हूं और यह बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है।''

सतीशन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया होता, तो यह अस्वाभाविक बात होती। उन्होंने आलोचकों पर पलटवार करते हुए कहा, ''वे किस दुनिया में रह रहे हैं?'' उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आलोचक उन सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं, जो पूजा-अर्चना के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। उन्होंने कहा, ''अधिकतर लोग मंदिर, चर्च और मस्जिद जाते हैं। क्या कोई यह कह सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए?'' सतीशन ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी अपनी ही पार्टी की अंदरूनी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके (विरोधियों के) पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे हताशा में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

मुंबई में कोस्टल रोड पर सुरंग में एक कार में आग लगी, कोई हताहत नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मुंबई में 'कोस्टल रोड' की सुरंग के अंदर बुधवार दोपहर एक कार में आग लग गई जिससे वहां वाहन चालकों में घबराहट फैल गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि आग बुझाने में करीब 20 मिनट लगे और इस बीच अन्य गाड़ी वाले दहशत में आ गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

अधिकारियों का कहना है कि जलती हुई कार के पीछे कई गाड़ियां फंस गईं, जिससे कुछ देर के लिए सड़क पर अफरातफरी मच गई।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर हाजी अली से वर्ली की ओर जाने वाली 'साउथबाउंड टनल' में हुई। उन्होंने कहा कि चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद अग्निशमन दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तथा 108 एम्बुलेंस सेवा को भी भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने में करीब बीस मिनट का समय लगा। उन्होंने कहा कि आग की वजह का तत्काल पता नहीं चल पाया है। आग बुझ जाने के बाद सुरंग में गाड़ियों की आवाजाही बहाल हो गयी। एक चश्मदीद ने इस घटना को एक सबसे भयावह अनुभव बताया है। 'फेडरेशन ऑफ़ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन' के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा, ''कुछ ही सेकंड में यातायात थम गया और लोग अपनी कारें छोड़कर भागने लगे। चारों तरफ चीख-पुकार, घबराहट और अफरातफरी का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो हॉलीवुड की किसी विध्वंसकारी फिल्म का दृश्य हो।'' जब आग लगी तब शाह भी उसी सुरंग के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे थे। शाह ने कहा कि उस समय सुरंग के अंदर पूरी तरह अफरातफरी मची गयी थी, वह एक गाड़ी वाले से लिफ़्ट लेकर वर्ली तक पहुंचे और फिर दक्षिण मुंबई जाने के लिए टैक्सी ली।

शाह ने महाराष्ट्र सरकार से सुरंग के अंदर आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने की अपील की, जिसमें निकासी संबंधी संकेतों में सुधार, जन जागरूकता और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने वाहन चालकों के लिए आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने के तरीके जानने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा को बुधवार को आगे बढ़ा दिया और अब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन अब पांच अगस्त के बजाय 17 अगस्त को किया जाएगा। इसी तरह, घर-घर जाकर सत्यापन करने की प्रक्रिया अब आठ अगस्त तक जारी रहेगी, जो पहले 29 जुलाई तक के लिए निर्धारित थी।

दिल्ली एसआईआर के तीसरे चरण का हिस्सा है, जिसे 14 मई को शुरू किया था। तीसरा चरण पूरा होने के बाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अतीत में विभिन्न कारणों से एसआईआर कार्यक्रमों में अक्सर बदलाव देखने को मिले हैं।

यूसीसी पर मोहन यादव बोले, यदि रामचंद्र एक विवाह करता है, तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार विधानसभा के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए और अगर रामचंद्र नामक कोई व्यक्ति एक शादी करता है, तो रहीम नाम के किसी शख्स से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। यादव, इंदौर के जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरों वाले नये भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस भवन के निर्माण में 83.13 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने प्रदेश भर में यूसीसी पर सभी धर्मों, सभी वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से संवाद किया तथा 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव एकत्र किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए कानून-कायदे अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा, ''जब हमारा देश एक है, तो अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? अगर रामचंद्र नामक कोई व्यक्ति एक शादी करता है, तो रहीम नाम के किसी शख्स से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है।''

सरकारी कर्मचारियों की आधिकारिक पहचान निजी जानकारी नहीं हो सकती : सीआईसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे लोक सेवकों की पहचान को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत निजी जानकारी नहीं माना जा सकता। सीआईसी ने यह फैसला रेलवे को दो अलग-अलग मामलों में यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) के नाम और पदनाम सार्वजनिक करने का निर्देश देते हुए सुनाया।

सूचना आयुक्त स्वागत दास ने उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के खिलाफ अलग-अलग सुनाए गए फैसलों में कहा कि रेलवे ने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे टीटीई के नाम और पदनाम बताने से इनकार करने के लिए आरटीआई कानून की धारा 8(ए)(जे) के तहत हासिल छूट का गलत इस्तेमाल किया।

इनमें से एक मामला उदयपुर एक्सप्रेस में तैनात एक टीटीई से जुड़ा हुआ था, जिसमें अपील करने वाले ने अधिकारी के नाम और पद के साथ-साथ उनसे जुड़ी शिकायतों, सतर्कता रिकॉर्ड, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा से जुड़ी अन्य जानकारियां मांगी थीं। वहीं, दूसरा मामला असरवा-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से संबंधित था, जिसमें अपीलकर्ता ने ड्यूटी पर तैनात टीटीई का नाम, कर्मचारी आईडी और पदनाम जानना चाहा था। दास ने दोनों ही मामलों में रेलवे की दलीलों को खारिज करते हुए कहा, सार्वजनिक सेवा में अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे किसी लोक सेवक की पहचान उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से जुड़ी जानकारी होती है और इसे आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत छूट प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी' नहीं माना जा सकता।

सीआईसी ने कहा कि लोक सेवकों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आरटीआई कानून के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। उसने कहा कि ऐसी बुनियादी जानकारी देने से इनकार करना कानून के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कमी को बढ़ावा देगा। आयोग ने संबंधित सीपीआईओ को निर्देश दिया कि वे संबंधित टीटीई के नाम और पद से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएं।

ओवैसी ने मतदाताओं से 20 जुलाई तक एसआईआर फॉर्म जमा करने की अपील की

हैदराबाद/भाषा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोगों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत गणना प्रपत्र अंतिम तिथि से काफी पहले जमा करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता से जुड़ी हुई है। ओवैसी ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम ने हैदराबाद के मुस्लिम युवा की मदद से एक ऐप तैयार किया है, जिसे मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में सहायता देने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने कहा, ''...हम आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि आपके लिए एसआईआर प्रपत्र भरना आसान हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया नागरिकता से जुड़ी हुई है।''

कडपा में डालमिया भारत के सीमेंट संयंत्र की आधारशिला रखी गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कडपा/भाषा। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को डालमिया भारत कंपनी के 3,100 करोड़ रुपये से प्रस्तावित दूसरे सीमेंट विनिर्माण संयंत्र की यहां आधारशिला रखी। कंपनी का यह नया संयंत्र हरित सीमेंट उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके 2027-28 की तीसरी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है। यह दक्षिण भारत में डालमिया भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विनिर्माण इकाई होगी, जिसकी क्लिंकर क्षमता 61 लाख टन प्रतिवर्ष और सीमेंट उत्पादन क्षमता 96 लाख टन सालाना की होगी।

इस अवसर पर लोकेश ने कहा, डालमिया भारत आंध्र प्रदेश के लिए एक मजबूत साझेदार है, जो टिकाऊ औद्योगिकीकरण के जरिये वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के दृष्टिकोण को साझा करती है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश हरित प्रौद्योगिकी आधारित विकास का वैश्विक मानक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बयान के मुताबिक, यह संयंत्र 80 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होगा और इससे करीब 1,000 रोजगार सृजित होंगे।

शिंदे ने परिसीमन का समर्थन किया, बेहतर शासन और विकास के लिए जरूरी बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा कि उक्त प्रक्रिया बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को न्याय दिलाने और विकास का लाभ उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जरूरी है। शिंदे ने भरोसा जताया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएंगे।

शिंदे ने हाल में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) छोड़ उनके नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले छह सांसदों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी अब 20-25 लाख हो गई है, जिससे सांसदों के लिए विकास संबंधी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। शिंदे ने कहा, परिसीमन जरूरी है, ताकि बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके और विकास का लाभ उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए शिवसेना प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विधेयक को पेश करने का साहस दिखाया है, जो लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद के पिछले सत्र में इस विधेयक को रोका था, लेकिन अब सभी दलों को आगामी सत्र में इसका समर्थन करना चाहिए। 2029 में संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक किए जाने के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इस विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। शाह के साथ मुलाकात के बारे में शिंदे ने कहा कि बातचीत उन निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर केंद्रित थी, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद शिवसेना (उबाठा) छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। इनमें मराठवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं, रेलवे और सड़क अवसंरचना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और अन्य लंबित प्रस्ताव शामिल हैं।

मलप्पुरम में मूंगफली गले में फंसने से तीन वर्षीय बच्चे की मौत

मलप्पुरम/भाषा। केरल के मलप्पुरम जिले में तीन वर्षीय एक बच्चे के गले में मूंगफली फंस जाने से दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को कुन्नुमपुरम इलाके में हुई। वेंगारा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, बच्चा घर पर नमकीन खा रहा था। इसी दौरान उसमें मौजूद एक मूंगफली उसके गले में फंस गई जिससे उसका दम घुटने लगा। पुलिस ने बताया कि बच्चे को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी राजद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं : उच्च न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचित लोकतंत्र में सरकार या शासन के किसी भी सांविधिक निकाय के खिलाफ नारेबाजी करना नागरिकों पर राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना केवल असहमति व्यक्त करने का एक माध्यम है, न कि नफरत, अवमानना या असंतोष का भाव। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई एक घटना से जुड़े मामले में कैथल के चार निवासियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन दंगा तो हो सकता है, लेकिन इस तरह की हिंसक गतिविधियों को सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना पैदा करने वाले कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। कैथल के कलायत थाने में 25 अगस्त, 2017 को दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए (राजद्रोह), 188 (कानूनी आदेश की अवहेलना), 120-बी (आपराधिक साजिश) समेत सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं। पंचकूला की एक अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा में, हरियाणा के कैथल में भीड़ ने बिजली विभाग के दफ़्तर में कथित तौर पर तोड़-फोड़ की।

न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 23 सितंबर, 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया था।

10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आईटीआई पूरा करने वालों को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को घोषणा की कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के समकक्ष माना जाएगा। सावंत ने गोवा बोर्ड समकक्षता प्रमाणपत्र शुरू करने तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच मजबूत तालमेल कायम करने समेत आईटीआई शिक्षा में बड़े सुधारों की घोषणा की। इससे उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संभावनाएं बेहतर होंगी।

मुख्यमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा अब 10वीं के साथ दो वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण वालों के समकक्ष माना जाएगा तथा उन्हें गोवा बोर्ड समकक्षता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आईटीआई और महाविद्यालयों के बीच समन्वय भी स्थापित किया है, ताकि व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें। सावंत ने कहा, इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईटीआई विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों के समान शैक्षणिक मान्यता मिले और उनकी रोजगार क्षमता भी बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत को प्रतिभा और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कौशल विकास एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उन्होंने कहा कि 'स्किल इंडिया मिशन', प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसी पहल युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान कर रही हैं तथा उन्हें रोजगार के उभरते अवसरों के लिए तैयार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं में अधिक निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा, कौशल और नवाचार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना ''विकसित भारत'' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक है।

सातवीं कक्षा के छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर प्रताड़ना और पिटाई का शिकार होने के बाद सातवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई। आत्मघाती कदम उठाने से पहले छात्र ने अपनी बहन को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने बताया कि छात्र यहां मरियप्पनपाल्या इलाके के एक स्कूल में पढ़ता है। उसने बताया कि आत्महत्या के कथित प्रयास के बाद छात्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि एक अन्य छात्र के साथ की गई किसी कथित शरारत को लेकर शिक्षक ने उसे फटकार लगाई थी और कक्षा से बाहर जाने को कहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्र के पिता की शिकायत पर ज्ञानभारती थाने में स्कूल प्रबंधन के सचिव, प्रधानाचार्य और दो से तीन शिक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 14 जुलाई को स्कूल के संस्थापक सचिव, प्रधानाचार्य और दो-तीन शिक्षकों ने किसी अज्ञात वजह से छात्र पर अपना गुस्सा निकाला और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आईं। शिकायत में कहा गया है, पिटाई के कारण हुए अत्यधिक दर्द और डर की वजह से मेरे बेटे ने उसी शाम फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से उनका बेटा लगातार स्कूल जाने से मना कर रहा था। छात्र का कहना था कि शिक्षक, प्रधानाचार्य, स्कूल प्रबंधन के सचिव और यहां तक कि अन्य छात्रों के माता-पिता भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पिता ने बताया कि वह अपने बेटे को लगातार समझा-बुझा रहे थे और उन्होंने वादा किया था कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के बाद वे उसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करा देंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा, पिता की शिकायत के आधार पर हमने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं।

अपार्टमेंट मालिकों से परामर्श के बाद ही विधेयक लाएगी सरकार : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को अपार्टमेंट मालिकों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी हितधारकों से परामर्श के बाद उनके स्वामित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाएगी। शिवकुमार ने कहा कि प्रस्तावित कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने से पहले इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बेंगलूरु में अपार्टमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि सरकार बिल्डर, संपत्ति दस्तावेजों और अपार्टमेंट प्रबंधन से जुड़े लंबित मुद्दों का भी समाधान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि घर खरीदने वालों के हित सुरक्षित रहें।

उन्होंने कहा, ''हम इस मामले में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जब आपको संपत्ति दी जा रही है तो उस पर आपका अधिकार होना चाहिए। आप ही उसके मालिक हैं।'' इसके साथ ही उन्होंने अपार्टमेंट मालिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून को जल्दबाजी में नहीं लाएगी और अंतिम रूप देने से पहले अपार्टमेंट एसोसिएशन, बिल्डर, विधि विशेषज्ञों तथा राजनीतिक दलों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

उन्होंने कहा, ''विधानसभा सत्र से पहले हमारे पास समय है। विधेयक पहले मंत्रिमंडल के पास जाएगा और उसके बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। मैं इसे जल्दबाजी में विधानसभा से पारित नहीं कराना चाहता। मैं सभी हितधारकों से चर्चा करना चाहता हूं और जहां भी अच्छे सुझाव मिलेंगे, उन्हें शामिल किया जाएगा।'' शिवकुमार ने कहा कि अपार्टमेंट मालिकों ने जीवनभर की कमाई से अपना घर खरीदा है और उन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति को पूरा कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इसका किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।''

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो बिल्डर खरीदारों को संपत्ति के मूल दस्तावेज नहीं सौंपेंगे, उन्हें चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बैंकों में संपत्ति गिरवी रखने के बाद भी दस्तावेज अपने पास रखने की प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी दी। शिवकुमार ने कहा कि सरकार की प्रस्तावित 'भूमि गारंटी', जिसे उन्होंने सरकार की छठी गारंटी बताया, के तहत संपत्ति मालिकों को बिना रिश्वत दिए 'खाता' प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 40 लाख संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और '26 लाख खाता' जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने अपार्टमेंट एसोसिएशन से सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) का समुचित रखरखाव करने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान में सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पेयजल आपूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान बेंगलूरु की आबादी लगभग 70 लाख थी, जो अब बढ़कर करीब 1.4 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि वहीं, लगभग 1.35 करोड़ वाहन उसी सड़क नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बुनियादी ढांचे का विस्तार चरणबद्ध तरीके से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेंगलूरु से जुड़े विभिन्न विभागों के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं तथा सड़कों के सुधार और गड्ढों की मरम्मत के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

शिवकुमार ने कहा कि सरकार छोटी-छोटी आवासीय कॉलोनियों के बजाय सुनियोजित बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की अपनी योजना पर कायम है। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहरों की तुलना में बेंगलूरु में आवास अब भी काफी सस्ता है, इसलिए यह शहर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''हमारा सपना है कि बेंगलूरु आपके दिल में बसे और वास्तव में भारत का भी दिल बने।''

इससे पहले बेंगलूरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि यह परामर्श बैठक मुख्य रूप से प्रस्तावित विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए बुलाई गई है और प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपनी टिप्पणियां विधेयक तक ही सीमित रखें। बायरे गौड़ा ने कहा कि प्रस्तावित कानून की प्रमुख विशेषताएं ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी और हितधारक एक निर्धारित ईमेल पते के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले विधि क्षेत्र के संगठनों तथा कानून निर्माण से जुड़े अन्य संस्थानों से भी परामर्श किया जाएगा।

डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हुईं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बुधवार के दिल्ली दौरे से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वह कांग्रेस आलाकमान के साथ अपने मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। उनकी यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मंत्रिमंडल में शामिल होने के इच्छुक नेता जोर-शोर से लामबंदी कर रहे हैं। मीडिया को साझा किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, शिवकुमार बुधवार शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। शिवकुमार रात में दिल्ली में ही ठहर सकते हैं, जबकि उनकी वापसी फिलहाल निर्धारित नहीं है। हालांकि, उनके दौरे की योजना में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों का मानना है कि वह नेतृत्व से बातचीत करेंगे।

शिवकुमार ने सोमवार को कहा था कि जब कांग्रेस आलाकमान उन्हें मिलने का समय देगा, तब वह दिल्ली जाएंगे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था, ''जब भी वे (पार्टी के शीर्ष नेता) मुझे समय देंगे, मैं जाऊंगा। वे मुझे अगले तीन या चार दिन में कोई तारीख देंगे। जैसे ही वह तारीख देंगे, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सोमवार को कहा था कि वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद उनसे बातचीत की जायेगी और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र किया जाएगा। दिल्ली रवाना होने से पहले, शिवकुमार ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या से मुलाकात की।

सिद्दरामय्या के बेटे एवं मंत्री यतींद्र सिद्दरामय्या ने मैसूरू में पत्रकारों से कहा , हम इसे (मंत्रिमंडल विस्तार को) जल्द से जल्द करना चाहते हैं। राज्यसभा और विधानपरिषद के चुनावों के कारण इसमें देरी हुई। आलाकमान दिल्ली में है और उसने राज्य के नेताओं को बुलाया है। बातचीत के बाद जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। मेरे पिता और मुख्यमंत्री (दिल्ली) जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के मानदंडों के बारे में पूछे जाने पर यतींद्र ने कहा, मुझे नहीं पता है। आपको इस बारे में मुख्यमंत्री, सिद्दरामय्या और आलाकमान से पूछना चाहिए। शिवकुमार ने तीन जून को मुख्यमंत्री पद और 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले 28 मई को सिद्दरामय्या ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

कर्नाटक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम मंत्रियों की संख्या 34 हो सकती है। अभी की स्थिति के अनुसार 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवकुमार पर मंत्रिमंडल का विस्तार करने का दबाव बढ़ रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मंत्री बनने के लिए कई दावेदार हैं और पद सीमित हैं ऐसे में शिवकुमार के लिए यह स्थिति काफी मुश्किल भरी है। शिवकुमार को जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत होगी। राज्य में सूखे के हालात के बीच मंत्रिमंडल विस्तार में देरी' को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और उसने सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर अंदरुनी कलह का आरोप लगाया है।

भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पीआरसी अधिसूचना तुरंत वापस लेने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार की स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) संबंधी अधिसूचना को तुरंत वापस लेने और इस मामले में उचित संवैधानिक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

पार्टी ने कहा कि इस अधिसूचना से राज्य के हितों, भारत के संघीय ढांचे के सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार पात्र नागरिकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करेगी, ताकि वे राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पूरा कर सकें। इसके बाद राज्य के राजस्व विभाग ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह प्रमाणपत्र कर्नाटक में स्थायी निवास का प्रमाण होगा। नागरिक स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। भाजपा ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा, कर्नाटक सरकार की ओर से 26 जून, 2026 को स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अधिसूचना राज्य के हितों, संघीय ढांचे के सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकती है। इसलिए हम संविधान के संरक्षक के रूप में आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और उचित निर्देश जारी करें।

राज्यपाल से मिलने वाले भाजपा प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता सी नारायणस्वामी, विधान परिषद सदस्य एन. रवि कुमार और सी. टी. रवि सहित अन्य नेता शामिल थे। भाजपा ने कहा कि विदेशियों की पहचान, नागरिकता, भारत में विदेशियों के प्रवेश और आव्रजन से जुड़े मामले संविधान की संघ सूची के तहत केवल केंद्र सरकार के विधायी व कार्यकारी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पार्टी ने इसी आधार पर दलील दी कि राज्य सरकार के पास 'स्थायी निवासी' की नई श्रेणी बनाने का न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार।

कर्नाटक में भाजपा ने किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये सूखा राहत की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से मांग की है कि वह सूखा राहत के लिए उनकी सरकार द्वारा वास्तव में किए गए कार्यों का पारदर्शी ब्योरा उपलब्ध कराएं। विजयेंद्र ने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये सूखा मुआवजा देने की घोषणा करें। विजयेंद्र ने यह टिप्पणी शिवकुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे उस पत्र के जवाब में की, जिसमें राज्य में सूखे की पैदा हो रही स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल भेजने का अनुरोध किया गया था।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के जरिए राज्य में बारिश में 30 प्रतिशत की कमी, मानसून में देरी और कृषि, पेयजल एवं जलाशयों के स्तर पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया था।

शिवकुमार ने मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि कर्नाटक ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं लेकिन केंद्र द्वारा जल्द जमीनी आकलन किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समय पर हस्तक्षेप से स्थिति से निपटने के राज्य के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। विजयेंद्र ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर कहा, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, आप सूखा पड़ने पर प्रधानमंत्री को केवल पत्र लिखने के बजाय जनता को यह बताइए कि आपने और आपकी सरकार ने सूखा राहत के लिए वास्तव में क्या किया है। क्या आप भूल गए कि कलबुर्गी में समीक्षा बैठक के दौरान आपने सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त करने की बात कही थी? उन्होंने कहा कि राज्य में अब भी कोई पूर्णकालिक कृषि मंत्री नहीं है।

विजयेंद्र ने मंगलवार को कहा, राजस्व मंत्री (उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर) तुमकुरु से आगे नहीं जा रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे वन विभाग की बातें कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों के नाम बदलने में व्यस्त हैं। उद्योग मंत्री (एम. बी. पाटिल) कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं। गृह मंत्री (प्रियंक खरगे) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में व्यस्त हैं। परिवहन मंत्री (बी सुरेश) बसों में घूम रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिंचाई मंत्री (रामलिंगा रेड्डी) को अपने विभाग में कोई खास रुचि नहीं है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने दावा किया कि अंदरूनी संघर्षों के कारण प्रशासन ठप हो गया है और लोग यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए जिलों का दौरा कब करेंगे।

उन्होंने कहा, ''आप रियल एस्टेट कारोबार में व्यस्त हैं। जिलों में मंत्री मौजूद नहीं हैं और कर्नाटक विकास कार्यक्रम (केडीपी) की बैठकें भी नहीं हुई हैं।'' विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री से अपने रियल एस्टेट कारोबार के बजाय जनता की समस्याओं पर ''ध्यान देने'' का आग्रह करते हुए कहा, सूखा राहत दीजिए। प्रति एकड़ 50,000 रुपये सूखा मुआवजा दीजिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की स्थिति को लेकर चिंतित है।

विजयेंद्र ने कहा, ''केंद्रीय आकलन दल के आने तक कम से कम अंतरिम राहत दीजिए और सूखे का आकलन करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त कीजिए। भगवान तिरुपति बालाजी आपको सद्बुद्धि दें।''

एनसीडब्ल्यू ने कर्नाटक बस यौन उत्पीड़न मामले की जांच जल्द पूरी करने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बेंगलूरु। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने बुधवार को कहा कि उसने कर्नाटक में मंगलूरु-विट्ठल मार्ग पर चलने वाली एक निजी बस में कॉलेज छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि उसकी अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

आयोग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के मंगलुरु-विट्ठल मार्ग पर चलने वाली एक निजी बस में छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा, यह घटना महिलाओं की यात्रा सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। रहाटकर ने कर्नाटक के डीजीपी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मामले में लागू सभी कानूनी प्रावधानों के तहत विस्तृत आरोपपत्र शीघ्र दाखिल किया जाए और सीसीटीवी फुटेज तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सहित सभी डिजिटल एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए जाएं। उन्होंने सार्वजनिक और निजी बसों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने तथा बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कर्मचारियों का सत्यापन सुनिश्चित करने और महिला आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के नियमों का सख्ती से पालन कराने की भी मांग की। आयोग की अध्यक्ष ने प्रभावित छात्राओं के लिए उनकी निजता की रक्षा करते हुए मनोवैज्ञानिक परामर्श और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

आयोग ने राज्य पुलिस से सात दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह समय पर न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की लगातार निगरानी करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना नौ जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलूरु-विट्ठल मार्ग पर चलने वाली एक निजी बस में हुई थी। आरोप है कि बस के परिचालक ने छात्राओं के सामने अश्लील हरकतें कीं, स्वयं को अशोभनीय तरीके से उजागर किया और उनका यौन उत्पीड़न किया।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

निविदा सूचना संख्या / अधिसूचना संख्या एसडब्ल्यूआर-आरएसपी-एलसी-112-आरओबी-09 दिनांक: 08-07-2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न लिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य
कामसमुद्रम एवं बिसानट्टम	Rs. 23,46,81,645/-

स्टेशनों के मध्य कि.मी. 273/100-200 पर एलसी 112 के स्थान पर 1*42 मीटर कंपोजिट गर्डर (रेलवे स्पैन) + कामसमुद्रम सिटी साइड पर +11*18.71 मीटर पीएससी गर्डर + अप्पेनहल्ली पर 5*18.71 मीटर पीएससी गर्डर + 1*5.5*2.5 मीटर के एलएचएस तथा अन्य संबद्ध कार्यों सहित आरओबी का निर्माण (कंपोजिट कार्य)।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। : 30-07-2026 को 15.00 बजे तक

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in

उप मुख्य अभियंता /आरओबी

PUB/290/AAZ/PRB/SWR/2026-27

आसान टिकट बुकिंग, पीएनआर स्थिति एवं अन्य रेलवे सेवाओं के लिए रेलवन ऐप डाउनलोड करें।

South Western Railway - SWR SWRRLY SWRAILWAYHQ sw_railways

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-(आईआरईपीएस)निविदा सूचना सं. 15 यूबीएल 2026-27 दिनांक : 08-07-2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न लिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य
हुब्बली मंडल :	Rs. 5,16,46,645/-

बेलगावी स्टेशन पर रोड सं. 01 एवं 02, रोड सं. 03 एवं 04 तथा रोड सं. 04 एवं 05 के मध्य त्वरित जल प्रबंधन व्यवस्था का कार्य।

हुब्बली मंडल :	Rs. 4,87,40,588/-

होसपेटे स्टेशन पर त्वरित जल आपूर्ति सुविधा का प्रबंधन एवं 2.5 लाख लीटर क्षमता के ओएचटी तथा 3 लाख लीटर क्षमता के जीएलआर का निर्माण।

हुब्बली मंडल :	Rs. 2,89,98,148/-

एसडब्ल्यू-i) एडीईएन/बीएवाई क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपाउंड/बाउंड्री वॉल का निर्माण। एसडब्ल्यू-ii) एसएसई/वर्क्स/एचपीटी सेक्शन में स्टाफ क्वार्टर्स के चारों ओर प्रस्तावित कंपाउंड वॉल का निर्माण।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। : 06-08-2026 को 11.00 बजे तक

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in

वरिष्ठ मंडल अभियंता/ समन्वय/हुब्बली

PUB/291/AAZ/PRB/SWR/2026-27

आसान टिकट बुकिंग, पीएनआर स्थिति एवं अन्य रेलवे सेवाओं के लिए रेलवन ऐप डाउनलोड करें।

South Western Railway - SWR SWRRLY SWRAILWAYHQ sw_railways

भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
खेल विभाग /DEPARTMENT OF SPORTS
(युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)
मानव संसाधन प्रभाग-II

मुख्यालय, गेट संख्या-10 (पूर्व द्वार), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

फा.सं. -12/12/2026-66
दिनांक: 04.07.2026

भारतीय खेल प्राधिकरण के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती

भारतीय खेल प्राधिकरण(SAI), जो कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है, कर्मचारी चयन आयोग(SSC) द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2024 की पब्लिक डिस्क्लोजर सूची (PDL) के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों से कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (Junior Translation Officer) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार खुला रहेगा :

- आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 08.07.2026 (प्रातः 10:00 बजे)
- आवेदन की अंतिम तिथि : 23.07.2026 (सायं 05:00 बजे)

केवल कर्मचारी चयन आयोग(SSC) द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2024 की पब्लिक डिस्क्लोजर सूची (PDL) के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

भर्ती संबंधी विस्तृत विज्ञापन, पात्रता की शर्तें, आवश्यक निर्देश तथा ऑनलाइन आवेदन का संपर्क सूत्र भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट www.sportsauthorityofindia.nic.in पर उपलब्ध है।

भर्ती संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी hrd2.sai@gov.in पर विद्युत डाक (ई-मेल) के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

CBC 47103/11/0019/2627

नेता हंगामे से नहीं, तर्कपूर्ण बहस और गंभीर चर्चा से बनते हैं : ओम बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। विधानमंडल को राजनीतिक नेतृत्व की प्रशिक्षणशाला बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों से संसदीय परंपराओं का सम्मान करने तथा सार्थक बहस, अध्ययन और रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सदन में हंगामा करने से नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित तर्कपूर्ण बहस और गंभीर चर्चा से नेता तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसदीय परंपराएं राजस्थान विधानसभा से ही सीखी हैं और इसी सदन ने उन्हें विधायी मूल्यों की सीख दी, जो आज तक उनके सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन कर रही है।

बिरला ने कहा, विधानमंडलों में दिए गए भाषण और हुई बहसें इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और वर्षों तक उनका अध्ययन किया जाता है। कोई सदस्य जितना अधिक सुनेगा और अध्ययन करेगा, वह उतना ही बेहतर योगदान दे सकेगा। उन्होंने कहा कि विधानमंडल लोकतांत्रिक विमर्श का ऐसा मंच है, जहां सरकार पूरे राज्य के लोगों की अपेक्षाओं, समस्याओं, आलोचनाओं और चुनौतियों को समझ सकती है। उन्होंने कहा, यदि सरकार सदन में उठाए गए मुद्दों का गंभीरता से अध्ययन करे तो समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर उनके प्रभावी समाधान तलाशे जा सकते हैं।

बिरला ने राजस्थान विधानसभा को विधायी मूल्यों की पाठशाला बताते हुए कहा कि यह जनप्रतिनिधियों के पूरे राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सटीक और स्पष्ट उत्तर दें। उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसद ऐसे मंच हैं, जहां से राज्य और देश के नेतृत्व का निर्माण होता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, जनता जवाबदेह और पारदर्शी शासन चाहती है। जो सरकारें और जनप्रतिनिधि इन मूल्यों का पालन करेंगे, वही सफल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने ऐतिहासिक कानून बनाकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नवाचार के जरिए देश की अग्रणी विधान संस्थाओं में अपनी पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोकतंत्र और जनसेवा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा की कार्यवाही से हर पीढ़ी सीखती है। सदन में ऐसी बहस और विचार होने चाहिए, जो राजस्थान के विकास में योगदान दें और आने वाली पीढ़ियों द्वारा भी याद किए जाएं।

उन्होंने कहा कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों के आचरण, समर्पण और कार्यशैली पर लगातार नजर रखती है। इसलिए सभी विधायकों को आत्ममंथन करते हुए जनता के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा वह संस्था है, जहां जनता के कल्याण के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायकों की भूमिका कमजोर हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में कई विधेयक पर्याप्त चर्चा के बिना और हंगामे के बीच पारित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विधायकों को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। जूली ने विधानसभा की बैठकों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की।

उन्होंने कहा, हमें विधानसभा को और मजबूत बनाना होगा। जब विधानसभा अपने 100 वर्ष पूरे करे, तब बैठकों की संख्या और सार्थक बहस के मामले में यह, देश में प्रथम स्थान पर हो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र विचारों की सतत बहने वाली गंगा है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास पर केंद्रित होने का अवसर देते हैं। देवनानी ने कहा, लोकतंत्र विचारों की निरंतर बहने वाली गंगा है। ऐसे कार्यक्रम अधिक होने चाहिए। जब हम इस तरह एक मंच पर आते हैं तो राजनीतिक मतभेद पीछे छूट जाते हैं और राजस्थान का विकास हमारा साझा एजेंडा बन जाता है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष समारोह का उद्देश्य लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, संवाद को प्रोत्साहित करना और राज्य के विकास के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व विधायक भी उपस्थित थे।

बीकानेर के सरकारी अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। बीकानेर के सरकारी प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पीबीएम) अस्पताल में ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव होने के बाद एक महीने से अधिक समय तक इलाज कराने वाली 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हाल के समय में इस अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के बाद मौत की यह तीसरी घटना है, जिसके साथ ही पिछले तीन महीने में राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा 19 हो गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घिया ने बताया कि कमला मेघवाल नामक महिला को आठ जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि महिला को मधुमेह था और यह उसकी तीसरी गर्भावस्था थी। डॉ. घिया ने कहा, चिकित्सकों की एक टीम ने उसका इलाज किया। एक समय उसकी हालत में सुधार भी हुआ था लेकिन बाद में अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और मेडिकल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में प्रसव के बाद जिन छह महिलाओं की हालत बिगड़ी थी उनमें से तीन की मौत हो गई है, जबकि बाकी तीन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

मेघवाल से पहले इसी अस्पताल में प्रसव के बाद ऐसी ही दिक्कतों के कारण कुछ हफ्ते पहले दो अन्य महिलाओं की मौत हुई थी। 19 जून को बीकानेर में प्रसव के बाद दिक्कतों का सामना करने वाली छह महिलाओं में से 20 साल की प्रीति की सबसे पहले मौत हुई थी। दो दिन बाद 26 साल की शारदा की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तीनों महिलाओं को ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर पेशाब आना बंद हो गया था।

पिछले तीन महीने में राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के 19 मामलों में से कोटा में पांच, बीकानेर में तीन, जोधपुर में दो और भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में नौ मामले दर्ज किए गए हैं। पीबीएम अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेघवाल को प्रसव के दिन ही भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जच्चा-बच्चा दोनों ठीक थे, लेकिन चूंकि महिला को मधुमेह था और पहले भी दो बार ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव हो चुका था इसलिए चिकित्सकों ने इस बार भी ऑपरेशन से प्रसव का सुझाव दिया और यह प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि, अगले ही दिन यानी नौ जून को उसे कुछ दिक्कतें हुईं और उसे डायलिसिस पर रखा गया। अधिकारी ने बताया कि महिला की हालत में कुछ समय के लिए सुधार हुआ और 'वेंटिलेटर सपोर्ट' हटा लिया गया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद उसके 'सी-सेक्शन' के टांकों से जुड़ी एक और सर्जरी हुई लेकिन कई अंगों के काम करना बंद करने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस बीच, पीबीएम अस्पताल में जान गंवाने वाली मेघवाल के परिजनों और कई संगठनों के सदस्यों ने बुधवार को मुर्दाघर के बाहर प्रदर्शन किया। महिला के रिश्तेदार बुधवार सुबह से ही मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक मेघवाल को न्याय नहीं मिलता, यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महिला के पति ने भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सकों ने सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि मेघवाल का अस्पताल की गहन उपचार इकाई (आईसीयू) में लगभग एक महीने तक इलाज किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने बांसवाड़ा जिला अस्पताल का दौरा किया

जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को बांसवाड़ा जिला अस्पताल का दौरा किया और चार महिलाओं की मौत के मामले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जिन चार महिलाओं की मौत हुई है, उनमें से एक महिला पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खींवसर ने बाद में अस्पताल के प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और मातृत्व वार्ड का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड एकत्र कर लिए गए हैं और उनकी जयपुर में अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के चिकित्सक मौजूद रहे।

एसएमएस अस्पताल में कटे जननांग को सर्जरी से ठीक किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) में डॉक्टरों ने धारदार हथियार के हमले में एक युवक के लगभग पूरी तरह कट गए जननांग को जटिल सर्जरी के जरिए ठीक किया गया। करीब 40 दिन के उपचार के बाद युवक की हालत अब सामान्य है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, 29 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसका जननांग लगभग पूरी तरह कट गया था। घटना के करीब चार घंटे के भीतर उसे एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभाग की टीम ने उसी रात आपातकालीन सर्जरी की।

यह जटिल ऑपरेशन प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन के मार्गदर्शन में इकाई प्रमुख डॉ. संगीता ठाकुरानी की टीम ने किया जिसमें डॉ. मुकुल धाभाई, डॉ. नवप्रीत और डॉ. ईशिता गौर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पताल के अनुसार, सर्जरी के दौरान क्षतिग्रस्त मूत्रमार्ग, स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा की सूक्ष्म स्तर पर मरम्मत की गई। ऑपरेशन के बाद लगातार निगरानी और विशेषज्ञ उपचार के कारण अंग की कार्यक्षमता सुरक्षित रही। करीब 40 दिनों के इलाज के बाद मरीज सामान्य रूप से मूत्र त्याग करने में सक्षम हो गया।

डॉ. राकेश कुमार जैन ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं, औद्योगिक हादसों, अंग कटने, जलने की चोटों, कैंसर के बाद अंगों के पुनर्निर्माण और जन्मजात विकृतियों के उपचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन शरीर के पुनर्निर्माण के साथ मरीज का आत्मविश्वास और सम्मान भी वापस लाने का काम करते हैं।

डॉ. संगीता ठाकुरानी ने कहा कि ऐसे मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि मरीज को चोट लगने के कुछ घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचाने से उपचार सफल हो सका। उन्होंने लोगों से अपील की कि गंभीर चोट, अंग कटने या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल विशेषज्ञ अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर उपचार से कई बार ऐसे अंगों को भी बचाया जा सकता है जिन्हें खोया हुआ मान लिया जाता है।

सरकार ने 18 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 18 अधिकारियों के तबादले किए हैं जिनमें महानिदेशक (डीजी) रैंक के दो अधिकारी भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने मंगलवार देर रात इस बारे में आदेश जारी किया। इसके तहत जोधपुर में नया पुलिस आयुक्त और अजमेर व भरतपुर में नए महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किए गए, साथ ही चार जिलों में नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए गए।

आदेश के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण व यातायात) अनिल पालीवाल को महानिदेशक व कमांडेंट जनरल (गृह रक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर काम कर रहीं मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक (यातायात) के पद पर लगाया गया है। जोधपुर के पुलिस आयुक्त शरत कविराज को महानिरीक्षक (अपराध) नियुक्त किया गया, जबकि विशेष शाखा (एसएसबी) के महानिरीक्षक अंशुमन भोमिया जोधपुर के नए पुलिस आयुक्त होंगे।

महानिरीक्षक (आयोजना) डॉ. रवि को पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज नियुक्त किया गया। उन्होंने राजेंद्र सिंह की जगह ली है जिन्हें पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक (सतर्कता) के पद पर भेजा गया। भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई का तबादला महानिरीक्षक (आयोजना) के पद पर किया गया जबकि महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रीति चंद्रा को भरतपुर रेंज का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। सरकार ने इस फेरबदल के तहत जोधपुर ग्रामीण, हनुमानगढ़, बालोतरा और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के तबादले भी किए हैं।

गैंगस्टर रोहित गोदारा का पुश्तैनी मकान रातों-रात ढहाया गया, पुलिस ने जांच शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। बीकानेर में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के पुश्तैनी मकान का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर अज्ञात लोगों ने रातों-रात ढहा दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार लूनकरनसर कस्बे के पास स्थित मकान में तोड़-फोड़ की घटना के वक्त कोई मौजूद नहीं था। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

लूनकरनसर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) रणवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मंगलवार सुबह इस घटना की जानकारी मिली जिसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि इमारत के बड़े हिस्से को ढहाने के लिए 'अर्थमूवर मशीन' (भारी मशीन) का इस्तेमाल किया गया था।

सिंह ने बताया कि आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस तोड़-फोड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इलाके में घर एक-दूसरे से काफी दूर-दूर बने हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निवासियों का मानना है कि घरों में चल रहे एयर कूलर के शोर के कारण मशीन की आवाज शायद किसी को सुनाई नहीं दी होगी।

पुलिस ने कहा कि घटना का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच की जा रही है। इस मकान में पहले गोदारा के पिता संत दास, मां गीता, भाई हनुमान स्वामी और हनुमान की पत्नी व बच्चे रहते थे। हालांकि तोड़-फोड़ के समय उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि गोदारा के माता-पिता और भाई फिलहाल जबरन वसूली के अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

हनुमान स्वामी को गंगानगर में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था जबकि उनके माता-पिता पर चुरू के रतनगढ़ में दर्ज एक अलग मामले में आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि गोदारा खुद गिरफ्तारी से बच रहा है और माना जा रहा है कि वह अभी अजरबैजान में है। अधिकारियों के अनुसार हनुमान की पत्नी 10-12 दिन पहले अपने बच्चों के साथ इस घर से चली गई थी और पड़ोसियों से खेतों की देखभाल करने का अनुरोध किया था। सिंह ने कहा कि तोड़-फोड़ के संबंध में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पिछले हफ्ते ऑपरेशन हार्डबॉल के सिलसिले में गोदारा का नाम सामने आया था। यह अभियान अमेरिका, कनाडा और यूरोप की प्रवर्तन एजेंसियों ने 'भारतीय संगठित अपराध नेटवर्क' के खिलाफ मिलकर चलाया था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इस अभियान में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या समेत कई अपराधों से जुड़े 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक गोदारा की पहचान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अपराध नेटवर्क के यूरोप मुखिया के तौर पर की गई है।

राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना

जयपुर। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर कमजोर होने के बीच राज्य में कई जगह आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार, आगामी कुछ दिनों में राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में 3040 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं।

बुधवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। राज्य के पश्चिमी भाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस अवधि में सबसे अधिक 18.0 मिलीमीटर बारिश अलवर में दर्ज की गई। सर्वाधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान गंगानगर में और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया।

ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठकों के लिए सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आगामी 6 एवं 7 अगस्त को जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठकों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं तय समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि आयोजन का सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हो सके। बुधवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों का विभागवार जायजा लिया तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात तथा इंडोनेशिया शामिल हैं। राजस्थान में आयोजित होने जा रही यह बैठक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जिसके लिए विभिन्न देशों के मंत्री एवं वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल जयपुर आएंगे। मुख्य सचिव ने गृह विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को एयरपोर्ट, आयोजन स्थल, होटल तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक प्रतिनिधिमंडलों के निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी मोटरकेड एवं यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा।

शराबबंदी का नियम तोड़ने पर युवक को बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने पर तथाकथित पंचों ने एक युवक को तालिबानी सजा दे डाली। पंचों ने युवक का पैर रस्सी से बांधकर उसे बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके साथ ही पीड़ित पर 11 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। यह खौफनाक वारदात करीब दो महीने पहले 12 मई 2026 को घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। नशे में पिता से अभद्र व्यवहार करने का था आरोपसायरा थानाधिकारी कानाराम सीरवी ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया- कमोल गांव के पंचों ने अपने स्तर पर गांव और भील बस्ती में शराबबंदी लागू कर रखी थी।

11 मई की रात को पीड़ित युवक चूनाराम गमेती ने कथित तौर पर शराब पी और नशे की हालत में अपने घर पहुंचा। घर पर जब उसके पिता ने उसे टोका, तो चूनाराम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उस पर पिता के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा। अगले दिन यानी 12 मई को समाज के कुछ पंचों ने इस मामले को लेकर भील बस्ती में एक बैठक (पंचायत) बुलाई। पंचायत में शराबबंदी का नियम तोड़ने और पिता से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में चूनाराम पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पंचों का गुस्सा सिर्फ जुर्माने पर शांत नहीं हुआ। सजा के नाम पर उन्होंने कानून हाथ में लेते हुए चूनाराम का एक पैर मजबूत रस्सी से बांधा और उसे सबके सामने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी बर्बरता का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो मंगलवार (14 जुलाई) को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीबी जी राम जी योजना से सशक्त होंगे गांव, साकार होगा विकसित भारत का संकल्प

जयपुर,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों के विकास से ही देश एवं प्रदेश का विकास होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रारम्भ की गई वीबी जी राम जी योजना विकसित भारत 2047 की मजबूत आधारशिला बनेगी तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के साथ ही गांवों में बुनियादी विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीबी जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश के ग्रामीण विकास का समग्र ब्लूप्रिंट तैयार करें। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाले स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।मैपिंग एवं रिकॉर्ड संधारण से सुनिश्चित हो पारदर्शिता- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में वीबी जी राम जी योजना क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य की बड़ी युवा आबादी कोई चुनौती नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल देकर जनसंख्या को आर्थिक विकास की शक्ति में बदल रही है।

विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस वर्ष यूनेस्को की थीम साझा भविष्य के लिए कौशल है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलें। आदित्यनाथ ने कहा, देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश को दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति होने पर गर्व है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतनी बड़ी आबादी चुनौती है या नहीं। यह हमारी ताकत है। हम युवाओं को कौशल देकर इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करेंगे और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। उन्होंने पिछली सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी (एसपी), पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई थी, कौशल विकास की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी और युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा, उस समय असुरक्षा का माहौल था। न महिलाएं सुरक्षित थीं, न व्यापारी। युवाओं की पहचान का संकट था। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं थे और राज्य के लोगों को बाहर अपनी पहचान के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों पर एक परिवार का कब्जा था और भर्ती में भ्रष्टाचार होता था।

उन्होंने कहा, अगर भर्तियां निकलती थीं तो 'चाचा-भतीजे की जोड़ी' पैसे वसूलने निकल पड़ती थी। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपजाऊ जमीन, भरपूर जल संसाधन और बड़े धार्मिक स्थलों के बावजूद उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा गया। उन्होंने कहा, प्रकृति ने हमें गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, नारायणी और सरयू जैसी नदियां दी हैं। हमारे पास अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, मनकामेश्वर धाम, शाकंभरी धाम और महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल हैं।

बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज के कई नेता भाजपा में शामिल हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को झटका देते हुए पिछले वर्ष पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई नेता बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर के.सी. सिन्हा और कुम्हरार व दीघा विधानसभा क्षेत्रों से जन सुराज के उम्मीदवार रहे क्रमशः रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मनेर सीट से जन सुराज के उम्मीदवार रहे गोपाल सिंह तथा पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर सिन्हा भी भाजपा में शामिल हुए। बांकीपुर में 30 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से है।

भाजपा में शामिल होने वाले संजय सरावगी ने पटना में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर पूरे देश में विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा में शामिल होने की होड़ लगी है। देशभर से लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोग लगातार संगठन के लिए काम करेंगे, जिससे भाजपा और मजबूत होगी। प्रोफेसर के.सी. सिन्हा ने कहा कि वह शिक्षा के माध्यम से भारत को फिर से ''सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने'' के उद्देश्य से भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भारत की आवाज पूरी दुनिया में और बुलंद हो सके। पूरा विश्व उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। भारत पहले भी विश्वगुरु रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से उस गौरव को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। रितेश रंजन सिंह ने कहा कि वह ''भावनाओं में बहकर'' जन सुराज में चले गए थे, जिसके लिए वह क्षमा चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी को भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।

मंत्रिमंडल ने एक करोड़ टन नई यूरिया क्षमता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य देश में एक करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले इस उर्वरक के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर नए निवेश ढांचे के तहत प्राकृतिक गैस आधारित आठ से नौ नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, पिछले एक दशक में छह नए संयंत्र स्थापित होने से यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई है। आठ से नौ नए संयंत्रों की स्थापना से देश अपनी पूरी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू स्तर पर कर सकेगा और इस उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि यूरिया की मांग हर साल लगभग पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में यूरिया का उत्पादन लगभग तीन करोड़ टन है जबकि मांग चार करोड़ टन है। एक करोड़ टन की कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। आज मंजूर की गई नीति का उद्देश्य अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वैष्णव ने कहा कि इस नीति के तीन प्रमुख स्तंभ -सब्सिडी की गणना के लिए स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत को अलग करना, यूरिया संयंत्र संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 12-16 प्रतिशत के बीच सुनिश्चित प्रतिफल और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 का विस्तार है। भारत की घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता वर्तमान में करीब 2.69 करोड़ टन है जबकि यूरिया का आयात करीब एक करोड़ टन है।

यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 दिन में दाखिल किया आरोप-पत्र

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के 11 दिन के भीतर ही आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने एक व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी आसिफ उर्फ हनी को इस मामले में एक महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। जनकपुरी थाने में बीएनएस की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके यौन उत्पीड़न), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाया और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप के अनुसार, आरोपी ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया, उसके साथ मारपीट की और उसकी निजी तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। प्राथमिकता के आधार पर जांच की गयी। अधिकारियों ने कहा कि सबूतों से संकेत मिला है कि दोनों लगातार संपर्क में थे और जांच के एक पहलू के तौर पर आरोपी के कार्यस्थल से उपस्थिति रिकॉर्ड एकत्र किए गए।

राष्ट्रपति मुर्मू ने आयुर्वेद विद्यार्थियों से आचार्य सुश्रुत के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से आचार्य सुश्रुत द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुसरण करने और चिकित्सा में नैतिकता तथा रोगियों के प्रति करुणामय सेवा के अपने संकल्प पर अडिग रहने का बुधवार को आग्रह किया। मुर्म ने साथ ही पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की वैश्विक स्वीकृति को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों को अपनाने की भी अपील की। सुश्रुत जयंती के मौके पर यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में आयोजित तीन दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम् 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को ईमानदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यावहारिक शोध करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी।

मुर्मू ने कहा, ''जहां भी उचित हो, उन्हें नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।'' उन्होंने उनसे आचार्य सुश्रुत द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने और चिकित्सा में नैतिकता तथा रोगियों के प्रति करुणामय सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान एआईआईए की एमआरआई इकाई का भी उद्घाटन किया। मुर्मू ने आयुर्वेद जगत को आचार्य सुश्रुत की जयंती पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सदियों पहले आचार्य सुश्रुत ने जब शल्य चिकित्सा पद्धति का सूत्रपात किया था, तब वह अपने समय की एक क्रांति से कम नहीं था। राष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

सोनम वांगचुक के अनशन की अनदेखी कर सरकार क्रूरता कर रही : अभिजीत दीपके

नई दिल्ली/भाषा। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बुधवार को अपनी भूख हड़ताल के 18वें दिन भी लगातार चिकित्सकीय निगरानी में हैं। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत नहीं करने को लेकर ''सरकार को क्रूर'' बताया। कॉजपा का मेडिकल की 'प्रवेश परीक्षा नीट' में कथित अनियमितताओं के विरोध में जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन बुधवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गया। कॉजपा की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, वांगचुक अभी भी ''बहुत कमजोर'' हैं और लगातार चिकित्सकीय निगरानी में हैं। वांगचुक का वजन घटकर 57.15 किलोग्राम रह गया है। पिछले 24 घंटे में उनका वजन 400 ग्राम कम हुआ है।

भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से अब तक उनका कुल वजन 8.9 किलोग्राम कम हो चुका है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, उनका रक्तचाप 105/76, रक्त शर्करा का स्तर 80 एमजी/डीएल और ऑक्सीजन संतृप्ति 97 प्रतिशत दर्ज की गई। शरीर में पानी का स्तर संतोषजनक बताया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि वह होश में हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी की आवश्यकता है। दीपके ने लिखा, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 18वां दिन है। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया, उसे सरकार की ओर से केवल चुप्पी मिली है। सरकार न केवल जवाबदेही से बच रही है, बल्कि वह क्रूर भी है।

ममता गुट बिड़ला तारामंडल के सामने कर सकती है रैली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को बिड़ला तारामंडल के पास 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' रैली आयोजित करने की अनुमति दे। टीएमसी कई वर्षों से मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करती आ रही है। उच्च न्यायालय ने विक्टोरिया हाउस के सामने से रैली का स्थान बदलकर बिड़ला तारामंडल के पास करने का आदेश मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और कानून-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से दिया।

अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वह टीएमसी के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली बिड़ला तारामंडल के सामने वाली सड़क पर आयोजित करने की अनुमति दे। कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में शहीद दिवस की दो अन्य रैलियां भी प्रस्तावित होने का उल्लेख करते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें। इलाके में एक रैली कांग्रेस की और दूसरी टीएमसी के प्रतिद्वंद्वी गुट की आयोजित होने वाली है।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को बिड़ला तारामंडल के सामने सड़क के एक हिस्से पर रैली आयोजित करने की अनुमति दे, जबकि सड़क के दूसरे हिस्से को वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखा जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पार्टी को यह प्रयास करना चाहिए कि रैली में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 2,500 तक सीमित रहे। कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया गया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाए, क्योंकि उसी दिन तीन अलग-अलग स्थानों पर तीन रैलियां आयोजित की जाएंगी।

अदालत ने निर्देश दिया कि यह रैली 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) को 20 कार्यकर्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत के आदेश का पालन हो। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नीत टीएमसी की ओर से एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने रैली आयोजित करने के अनुरोध को मंजूरी देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे उत्तर और मध्य कोलकाता को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो सकता है। शहीद दिवस रैली की अनुमति के लिए याचिका पेश करते हुए गुट के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह रैली दो या तीन साल को छोड़कर 1993 से ममता बनर्जी के नेतृत्व में मध्य कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित की जाती रही है।

पवार का शिंदे के कार्यालय में जाना महज संयोग, राजनीतिक मुलाकातों में साजिश का कोण न निकालें : सुले

मुंबई/भाषा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार द्वारा पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दफ्तर में अपने विधायकों के साथ की गई बैठक को लेकर लगाई जा रही अकटलों को बुधवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह घटना महज 'एक संयोग' थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बैठकों को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए और लोगों से अपील की कि वे यह सोचना बंद करें कि राजनीतिक नेताओं के बीच होने वाली हर बैठक किसी साजिश का हिस्सा होती है। पवार ने गत बुधवार (आठ जुलाई को) को मुंबई में विधान भवन परिसर में शिंदे के कार्यालय में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की थी।

वरिष्ठ नेता पवार लंबे समय से लंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार समिति के सदस्य के तौर पर एक बैठक में शामिल होने के लिए विधानसभा परिसर गए थे। राकांपा(शप) अध्यक्ष ने बैठक के बाद शिंदे से उनके चैंबर में जाकर मुलाकात की। राकांपा(शप)विपक्षी गठबंधन 'महा विकास अघाडी' (एमवीए) का हिस्सा है। इस बैठक से राजनीतिक अटकलें शुरू हो गईं और राकांपा (शप) की सहयोगी शिवसेना (उबाठा)ने भी इसकी आलोचना करते हुए इसे गद्दारों को महिमामंडित करने वाला कदम बताया। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने यह टिप्पणी शिंदे और उनकी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए की थी। सुले ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने पवार से आराम करने को कहा था, इसके बावजूद वह विधानसभा परिसर में गए।

केंद्र ने वाराणसी के लिए दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी, 25,500 करोड़ रुपये होगा निवेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वाराणसी के लिए दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर लगभग 25,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.22 किलोमीटर लंबे लिंक रोड के विकास को मंजूरी दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना में मुख्य सड़क मार्ग, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड समेत छह/चार-लेन वाला मुख्य रूप से एलिवेटेड गलियारा शामिल है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के तहत कुल 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत से पूरा करेगा। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली रूपरेखा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से देश में ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह गलियारा वाराणसी में भीड़ कम करने की योजना का एक अहम हिस्सा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच बिना रुकावट के संपर्क सुविधा देगा। साथ ही, इससे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाईअड्डा, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रामनगर पोर्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के घाटों और पास के चंदौली इलाके तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। बयान में कहा गया है कि 80-100 किमी/घंटा की गति के लिए डिजाइन की गयी इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। यानी इसमें लगभग 50 प्रतिशत की कमी आएगी। बयान में आगे कहा गया है कि इससे शहर के सड़क नेटवर्क पर भीड़ कम होगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, गाड़ियों को चलाने का खर्च कम होगा और यात्रियों तथा माल की आवाजाही तेज और बिना रुकावट के हो सकेगी। यह परियोजना एक आर्थिक केंद्र (चंदौली सामाजिक आर्थिक क्षेत्र), एक सामाजिक केंद्र (चंदौली) और छह बड़े लॉजिस्टिक केंद्रों तक पहुंच बेहतर बनाकर क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी। इससे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टीमॉडल' एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सीसीईए ने वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक गलियारा बनाने को भी मंजूरी दी है। यह गलियारा गंगा नदी के तट से जुड़ा होगा। बयान के अनुसार, 46.04 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में छह-लेन वाला एलिवेटेड मुख्य मार्ग, 'केबल-स्टेयड' पुल, 'फुट-ओवर ब्रिज'-के साथ बड़ा पुल, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड शामिल हैं।

असम में गरीबी कम करने में प्रत्यक्ष नकद अंतरण की अहम भूमिका : मुख्यमंत्री हिमंत

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य में गरीबी कम करने में प्रत्यक्ष नकद लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की बहुआयामी गरीबी दर को घटाकर एकल अंक (10% से कम) पर लाना है। विधानसभा में राज्य बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए शर्मा ने बताया कि असम में बहुआयामी गरीबी दर 2015 के 32.67% से घटकर अब 14.47% रह गई है। राज्य में गरीबी उन्मूलन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमारा लक्ष्य इसे (बहुआयामी गरीबी दर) घटाकर एकल अंक तक लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गरीबी पर सीधे प्रहार करना है तो डीबीटी सबसे प्रभावी माध्यम है। राज्य में विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार से मिले सहयोग के कारण उनकी सरकार व्यापक और परिवर्तनकारी विकास कार्य करने में सफल रही है। शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकारें गरीबी कम करने में इसलिए सफल नहीं हो सकीं क्योंकि उस समय लोगों के पास न तो बैंक खाते थे और न ही आधार की सुविधा उपलब्ध थी।

मथुरा विवाद : उच्चतम न्यायालय ने हिंदू पक्षों के बीच चर्चा होने के बीच सुनवाई टाली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह सूचित किये जाने पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टाल दी कि विभिन्न हिंदू पक्ष इस बात पर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस मामले में किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा।

उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2025 के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने अन्य वाद में एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना था। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त नियत की। ऐसा तब किया गया जब हिंदू पक्षों में से एक के वकील ने बताया कि वादियों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत चल रही है। आरंभ में खंडपीठ ने कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन तथा इस विवाद में एक अन्य हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील पीवी योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, अगर दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत चल रही है, तो हम मामले की सुनवाई टाल देंगे। योगेश्वरन ने पीठ से कहा कि वे नहीं चाहते कि अदालत बातचीत के बारे में आदेश में कुछ भी दर्ज करे, क्योंकि यह वादियों के बीच हो रही थी और 'अनौपचारिक' है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि मामले को कई बार स्थगित किया जा चुका है और इस बार इसे तभी स्थगित किया जा सकता है जब पक्षों के बीच कोई बात चल रही हो। पीठ ने वकीलों से कहा, ''हम पक्षों को बातचीत के लिए बाध्य नहीं करने जा रहे हैं। अगर कुछ चल रहा है, तो उसे आदेश में भी दर्ज किया जा सकता है। इसमें क्या हर्ज है?'' पीठ ने यह कहते हुए मामले को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्चतम न्यायालय पहले से ही मस्जिद समिति और हिंदू पक्षों की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें 26 मई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मथुरा की अदालत में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है।

सुविचार

अच्छे विचारों से मन सुंदर बनता है, अच्छे कर्मों से जीवन। दूसरों की सहायता करें, मुस्कान बांटें, खुशियाँ बढ़ती जाएँगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सुविधाओं के शत्रु

रेलवे के कई यात्रियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में एसी कोच से करोड़ों रुपए की चद्दर, कंबल, तकिया कवर आदि पार करने की घटनाएं शर्मनाक हैं। इन कोचों में यात्रा करने वाले लोगों के बारे में यह तर्क भी नहीं दिया जा सकता कि वे दैनिक जीवन में आर्थिक तंगी और चीजों की किल्लत के कारण ऐसा कर रहे हैं। रेलवे की संपत्ति यात्रियों की सुविधा के लिए है। कई यात्री इसे अपनी निजी संपत्ति समझकर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता पाया जाए, उससे संबंधित सामान की कीमत का कई गुणा जुर्माना वसूला जाए। रेलवे में उक्त चीजों की चोरी की घटनाओं से पता चलता है कि कई लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। ये जहां भी जाते हैं, अपना 'हुनर' दिखाते हैं। किसी जगह की सुंदरता को कैसे नष्ट करना है, साफ जगह पर कैसे गंदगी फैलानी है, कहीं पर व्यवस्था कैसे बिगाड़नी है – इन सब कार्यों में उन्हें महारत हासिल होती है। पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बाराती अपने घर लौटते वक्त कन्या पक्ष द्वारा किए गए इंतजाम को तहस-नहस करते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने चद्दर, गद्दे, तकिए आदि को मिलकर फाड़ दिया था। अगर इतनी एकता और बल का प्रदर्शन किसी सकारात्मक काम में करते तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होती। जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती है। वे व्यवस्था बिगाड़ने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।

भारत में अक्सर लोग शिकायतें करते हैं कि 'सरकार हमारे लिए सुविधाओं का निर्माण नहीं करती है ... उसे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता एवं स्वच्छता की परवाह नहीं है।' ये शिकायतें पूरी तरह निराधार नहीं हैं। कई जगह सरकारी प्रयासों में कमियां रहती हैं, लेकिन हर कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। जो लोग एसी कोच से चद्दर, कंबल, तकिया कवर उड़ा रहे हैं, क्या उन्हें सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है? व्यवस्था बिगाड़ने में लोगों के किरदार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के जयपुर शहर में सुंदर एवं कई सुविधाओं से युक्त नई बसें चली थीं। लोगों ने एक महीने में ही उनकी सूरत बिगाड़ दी। कहीं गुटखा-पान खाकर थूक दिया, किसी सीट को उधेड़ दिया, कहीं आपत्तिजनक शब्द लिख दिए – ये नजारे विभिन्न शहरों की बसों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। विद्यार्थी जीवन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बच्चों को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि हमें सार्वजनिक स्थानों एवं संसाधनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा कोई काम न करें, जिससे इनकी गुणवत्ता और अस्तित्व पर आंच आए। कुछ साल पहले एक स्कूल के बच्चे, जो बड़ी कक्षाओं से थे, राजस्थान के एक शहर में टेबल टेनिस का मैच खेलने गए। वहां उन्हें एक धर्मशाला में ठहराया गया। विद्यार्थियों ने मैच जीतने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वे हारकर धर्मशाला लौट आए। अचानक एक लड़के को खुराफात सूझी। उसने अपने साथियों को सुझाव दिया कि 'हम मैच हार गए, कोई बात नहीं ... अब इस धर्मशाला के कमरों में लगे बल्ब उतारकर ले चलते हैं।' उन लड़कों को हार की मायूसी सता रही थी। उन्हें ऐसी खुराफात में आनंद का स्रोत नजर आया। उन्होंने योजना के अनुसार कई कमरों के बल्ब उतार लिए। जब वे अपने गांव रवाना हुए तो धर्मशाला के प्रबंधक ने सबको रोक लिया। उसने भारी जुर्माना वसूला और स्कूल को सूचित कर दिया। इस घटना से उनकी बहुत किरकिरी हुई। वास्तव में, ऐसे लोगों को चोरी करने, व्यवस्था बिगाड़ने, किसी जगह की सुंदरता नष्ट करने में आनंद का स्रोत नज़र आता है। जिस दिन उन्हें अहसास हो जाएगा कि 'गलत हरकतें महंगी पड़ेंगी', वे इनसे तौबा कर लेंगे।

ट्वीटर टॉक

ज्ञान से बुद्धि, हुनर से तरक्की और अच्छी सेहत से हर संकल्प पूरा होता है। आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को अपना रहे हैं, जिससे देश की पहचान और भी मज़बूत हो रही है। धन का सबसे बड़ा रूप हुनर है; दौलत में सबसे बड़ा है सीखना।

–नरेन्द्र मोदी

यह ऐतिहासिक इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की आर्थिक ताकत, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और बढ़ती ताकत का एक मज़बूत सबूत है। इस एग्रीमेंट के ज़रिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को णघ मार्केट में बड़े पैमाने पर एक्सेस मिलेगा, एक्सपोर्ट को नई तेज़ी मिलेगी।

–दिया कुमारी

विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह सदन सिर्फ़ एक इमारत नहीं है; यह राजस्थान के लाखों लोगों की उम्मीदों और उनकी लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर है। यहां जनहित में 400 से ज़्यादा बिल पास हुए हैं।

–अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

नारी सशक्तीकरण

डॉ. अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को संपत्ति, विवाह, शिक्षा के मामलों में कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने बहुत सोच-विचार कर 'हिंदू कोड बिल' तैयार किया। इस बिल में उन्होंने प्रावधान रखे थे कि बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार हो, महिलाओं को तलाक का कानूनी अधिकार मिले एवं बहुविवाह समाप्त होकर एक पत्नी नियम लागू हो। उन्होंने जब इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया तो अनेक कट्टरपंथियों ने इसका जमकर विरोध किया। विरोधियों का कहना था कि यह बिल भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देगा। डॉ. अंबेडकर लगभग चार सालों तक बिल को पारित कराने के लिए प्रयास करते रहे। कालांतर में उन्होंने वर्ष 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि, 'मैं अपने पद पर बने रहने के बजाय महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना और इस्तीफा देना बेहतर समझता हूं।' आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। बाद में उनके सिद्धातों पर गौर कर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानून बने।

सामयिक

क्या भारत विरोध ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेला?

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो निवेश बढ़ सकता है, व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं, ऊर्जा सहयोग को गति मिल सकती है और करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तो विकास की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह का हालिया बयान दक्षिण एशिया की राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधे विरोध की नीति न अपनाता और भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ता, तो आज पाकिस्तान को कर्ज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का वातावरण बनता। किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता की ओर से इस प्रकार का आत्मविश्लेषण असामान्य माना जा रहा है क्योंकि दशकों से पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक सोच का बड़ा हिस्सा भारत विरोध पर आधारित रहा है। राणा सनाउल्लाह ने अपने बयान में वर्ष 2015 का उल्लेख किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस समय इसे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत की संभावना के रूप में देखा गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और उसके बाद दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान उस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा और इसके लिए स्वयं पाकिस्तान की राजनीतिक सोच तथा भारत विरोधी दृष्टिकोण जिम्मेदार रहा।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास विभाजन के समय से ही जटिल रहा है। दोनों देशों ने अनेक युद्ध देखे, सीमा पर लगातार तनाव बना रहा और आतंकवाद के मुद्दे ने विश्वास की कमी को और गहरा किया। कश्मीर विवाद ने भी संबंधों को सामान्य होने नहीं दिया। समय समय पर शांति वार्ताएं हुईं, व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए गए और सांस्कृतिक आदान प्रदान की पहल भी हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना संबंधों को पीछे धकेल देती रही। इस पृष्ठभूमि में किसी पाकिस्तानी वरिष्ठ नेता द्वारा यह स्वीकार करना कि अवसर गंवाया गया, अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ता राजकोषीय घाटा, महंगाई, ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बार बार सहायता लेने की मजबूरी ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि यदि दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़े और भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य हो, तो दोनों देशों को लाभ मिल सकता है। भारत विशाल बाजार है और पाकिस्तान की कई वस्तुओं के लिए निकटतम व्यापारिक साझेदार भी हो सकता है। इसी संदर्भ में राणा सनाउल्लाह का बयान आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत ने पिछले एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विनिर्माण और वैश्विक कूटनीति में उल्लेखनीय विस्तार किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से जूझता रहा है। यदि दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध होते तो सीमा पार व्यापार, परिवहन, ऊर्जा सहयोग और निवेश के नए अवसर विकसित हो सकते थे। दक्षिण एशिया विश्व की सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में गिना जाता है। इसका एक बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध भी हैं। राणा सनाउल्लाह ने यह भी संकेत दिया कि आज पाकिस्तान भारत से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वर्तमान परिस्थितियों में विश्वास की कमी बहुत अधिक है और पहले की तुलना में संवाद स्थापित करना कहीं अधिक कठिन हो गया है।

भारत का दृष्टिकोण भी पिछले कुछ वर्षों में अधिक स्पष्ट और कठोर हुआ है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होता, तब तक संबंधों का सामान्य होना कठिन है। इसी कारण व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद भी सीमित रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई तनावपूर्ण घटनाओं ने इस दूरी को और बढ़ाया है। राणा सनाउल्लाह का बयान केवल भारत की प्रशंसा भर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर भी टिप्पणी माना जा रहा है। पाकिस्तान में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं पर खर्च होता है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाते। यदि क्षेत्रीय तनाव कम हो तो संसाधनों का बेहतर उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है। इस दृष्टि से उनका बयान पाकिस्तान के भीतर चल रही व्यापक बहस को भी सामने लाता है।

दक्षिण एशिया विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी का घर है, लेकिन आर्थिक सहयोग के मामले में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित हों तो क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाई समानता और ऐतिहासिक संबंध भी सहयोग को मजबूत आधार दे सकते हैं। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती रही हैं। हालांकि केवल राजनीतिक इच्छा पर्याप्त नहीं होती। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम आवश्यक हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना, आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई, मानवीय मुद्दों का समाधान, मछुआरों और कैदियों की रिहाई, व्यापारिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना ऐसे उपाय हो सकते हैं जो धीरे धीरे विश्वास का वातावरण तैयार करें। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी क्योंकि दोनों देशों के बीच कई दशकों का अविश्वास मौजूद है।

राणा सनाउल्लाह के बयान पर पाकिस्तान के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसे यथार्थवादी स्वीकारोक्ति बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी माना। भारत में भी इस बयान को सावधानी के साथ देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सकारात्मक परिवर्तन का आकलन केवल बयानों से नहीं बल्कि व्यवहारिक कदमों से किया जाना चाहिए। जब तक दोनों देशों की नीतियों में ठोस बदलाव दिखाई नहीं देता, तब तक ऐसे वक्तव्यों को संभावनाओं के संकेत के रूप में ही देखा जाएगा। इतिहास यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सकारात्मक पहल हुई है। बस सेवा शुरू हुई, व्यापार बढ़ाने की कोशिश हुई, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ा।

लेकिन हर बार किसी बड़ी सुरक्षा घटना ने इन प्रयासों को झटका दिया। इसलिए भविष्य में यदि कोई नई शुरुआत होती है तो उसे अधिक मजबूत संस्थागत आधार और पारस्परिक विश्वास की आवश्यकता होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राणा सनाउल्लाह का बयान पाकिस्तान सरकार की किसी नई आधिकारिक नीति की घोषणा नहीं है। यह एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता का सार्वजनिक आकलन है, जिसे व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिर भी यह इस बात का संकेत अवश्य देता है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ राजनीतिक वर्ग अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि लगातार टकराव की नीति से अपेक्षित लाभ नहीं मिला और आर्थिक विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आवश्यक हो सकता है।

दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो निवेश बढ़ सकता है, व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं, ऊर्जा सहयोग को गति मिल सकती है और करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तो विकास की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी। राणा सनाउल्लाह का वक्तव्य इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह अतीत की नीतियों पर आत्मचिंतन का संकेत भी है और भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा भी। हालांकि वास्तविक परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस नीतिगत निर्णयों, विश्वास निर्माण के उपायों और निरंतर संवाद से ही संभव होगा। यदि दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित करते हुए साझा हितों पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं, तो न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरा दक्षिण एशिया अधिक शांत, समृद्ध और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

नजरिया

न्याय की भाषा अंग्रेज़ी, पीड़ित की भाषा हिंदी

प्रो. आरके जैन अरिजीत

सुप्रीम कोर्ट का हालिया प्रश्न – क्या अंग्रेज़ी को भारत की स्वदेशी भाषा माना जा सकता है?-सिर्फ न्यायालय का सवाल नहीं, भारत की भाषाई चेतना पर दस्तक है। यह बहस अंग्रेज़ी के पक्ष-विपक्ष की नहीं, उस मानसिकता की है जिसने आज़ादी के आठ दशक बाद भी भाषा को आत्मसम्मान नहीं, हैसियत का पैमाना बना रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई अंग्रेज़ी आज विश्वविद्यालयों, न्यायालयों, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख भाषा है। करोड़ों भारतीय इसे शिक्षा और रोज़गार का माध्यम बना चुके हैं, इसलिए इसे पूरी तरह विदेशी कहना यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा। पर क्या लंबे उपयोग से कोई भाषा स्वदेशी हो जाती है? यदि हाँ, तो स्वदेशी का आधार इतिहास होगा, संस्कृति या सुविधा? सुप्रीम कोर्ट ने भाषा नहीं, भारतीय आत्मविश्वास का प्रश्न उठाया है। वही आत्मविश्वास जिसने कभी संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया और सैकड़ों बोलियों के बल पर विश्व को ज्ञान दिया, लेकिन आज अपने ही देश में स्वयं को सिद्ध करने के लिए विदेशी भाषा का सहारा खोजता है। इस प्रश्न का सबसे बड़ा कटघरा हमारी न्याय व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों की कार्यवाही व निर्णय आज भी अंग्रेज़ी में होते हैं। विडंबना यह है कि न्याय उसी नागरिक के लिए लिखा जाता है, जो उसकी भाषा नहीं समझता। स्वयं न्यायालय भी मान चुका है कि फैसलों और आदेशों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है, क्योंकि न्याय तभी सार्थक है, जब वह जनता की भाषा में पहुंचे। फिर भी अदालतों में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व निर्विवाद है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यदि जनता की भाषा से दूर रहेगा, तो न्याय और नागरिक के बीच दूरी बनी रहेगी। क्या केवल वर्षों के प्रयोग से अंग्रेजी स्वदेशी हो जाएगी, या न्याय व्यवस्था को भारतीय भाषाओं से जोड़ना ही लोकतांत्रिक सुधार होगा? यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं, न्याय तक समान पहुंच का है।

आज का सबसे कठोर सत्य यह है कि अंग्रेज़ी भारत में केवल भाषा नहीं, वर्गीय शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। यही भाषा कुछ के लिए अवसरों का द्वार है, तो लाखों के लिए अदृश्य दीवार। महंगे विद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थाएं इसे योग्यता की पहली शर्त मानती हैं। वहीं गांव का प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दलित-बहुजन युवा और मातृभाषा में शिक्षित लाखों छात्र क्षमता नहीं, भाषा की बाधा से पीछे छूट जाते हैं। तीन-भाषा नीति पर वर्षों से जारी बहस और दक्षिण भारत का प्रतिरोध इसी भाषाई वर्चस्व की आशंका का संकेत है। यदि अंग्रेज़ी को स्वदेशी मान लेने से यह असमानता और गहरी होती है, तो क्या हम नई गुलामी को ही वैधता नहीं दे रहे? कभी सत्ता तलवार से चलती थी, आज भाषा के प्रमाणपत्र से चलती है। इतिहास इस बहस का सबसे ईमानदार साक्षी है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने स्पष्ट लिखा था कि उसका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना है, जो रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन विचार, नैतिकता, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज़ हों। यह केवल शिक्षा नीति नहीं, मानसिक उपनिवेश की योजना थी। स्वतंत्र भारत ने राजनीतिक आज़ादी तो पा ली, पर भाषाई स्वाधीनता का संघर्ष अधूरा रह गया। समय के साथ अंग्रेज़ी का स्वरूप भी बदला है। आज हिंग्लिश, तम्लिश, बेंग्लिश जैसी मिश्रित भाषाएं बताती हैं कि भारत हर भाषा को अपना रंग दे सकता है। अंग्रेज़ी भी अब भारतीय अनुभवों से समृद्ध है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह बदलाव हमारी 22 अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों बोलियों की कीमत पर हो रहा है? यदि नई पीढ़ी मातृभाषा से पहले अंग्रेज़ी में सोचने लगे, तो यह केवल भाषा का नहीं, सांस्कृतिक स्मृति के क्षरण का संकेत होगा।

दुनिया का अनुभव भारत को स्पष्ट संकेत देता है। जापान ने जापानी, जर्मनी ने जर्मन, फ्रांस ने फ्रांसीसी, चीन ने मंदारिन और इज़राइल ने पुनर्जीवित हिब्रू के बल पर ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्रीय पहचान को सशक्त बनाया। इन देशों ने अंग्रेज़ी सीखी, उसका उपयोग किया, लेकिन उसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। भारत का मार्ग टकराव नहीं, संतुलन का होना चाहिए। नई शिक्षा नीति मातृभाषा आधारित शिक्षा पर बल देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद, भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि की पढ़ाई और बहुभाषी डिजिटल ज्ञान-संसाधन बताते हैं कि ज्ञान अब अंग्रेज़ी की कैद में नहीं है। फिर अंग्रेज़ी को स्वदेशी घोषित करने की जल्दबाज़ी क्यों? असली चुनौती अंग्रेज़ी को हटाना नहीं, भारतीय भाषाओं को उस स्तर तक पहुंचाना है, जहाँ किसी विद्यार्थी का भविष्य उसकी भाषा नहीं, प्रतिभा तय करे। यहीं सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न सबसे अधिक दूरदर्शी बन जाता है। यह हिंदी बनाम अंग्रेज़ी, उत्तर बनाम दक्षिण या किसी भाषा की श्रेष्ठता का विवाद नहीं, उस भारत की खोज है जहाँ हर बच्चा मातृभाषा में सोच सके, क्षेत्रीय भाषा से समाज से जुड़े और अंग्रेज़ी के माध्यम से दुनिया से संवाद करे। यही बहुभाषिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अंग्रेज़ी को स्वदेशी कहकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई, तो लोकगीत, लोककथाएं, दर्शन, लोकविज्ञान, क्षेत्रीय साहित्य और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक स्मृतियां हाशिए पर चली जाएंगी। लेकिन यदि अंग्रेज़ी वैश्विक अवसरों की भाषा और भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय जीवन की आत्मा बनें, तो वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, परस्पर सहयोगी होंगी। भाषा का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सह-अस्तित्व सुरक्षित करेगा।

दरअसल, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि स्वदेशी का अर्थ केवल उत्पत्ति से है। भारत का इतिहास बताता है कि उसने अनेक संस्कृतियों, विचारों और भाषाओं को अपनाया, पर अपनी आत्मा कभी नहीं खोई। इसलिए न अंग्रेज़ी का विरोध समाधान है, न महिमामंडन। असली प्रश्न यह है कि निर्णय, ज्ञान और आने वाली पीढ़ी के सपनों की भाषा कौन होगी। यदि प्रशासन, न्याय, विज्ञान, चिकित्सा, शोध और तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो अंग्रेज़ी कभी चुनौती नहीं बनेगी। लेकिन यदि भारतीय भाषाएं घर, कविता और उत्सव तक सिमट गईं, और अंग्रेज़ी सत्ता, ज्ञान व अवसर की भाषा बन गई, तो वही मानसिक असमानता लौटेगी, जिसकी नींव औपनिवेशिक शासन ने रखी थी। गुलामी केवल विदेशी शासन से नहीं आती, वह तब भी आती है, जब कोई समाज अपनी भाषा पर विश्वास खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भाषाई निर्णय नहीं दिया, बल्कि भारत के सामने एक मूल प्रश्न रख दिया-क्या भाषा केवल सुविधा का माध्यम होगी या राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार? अंग्रेज़ी वैश्विक अवसरों का द्वार है, लेकिन भारत की सभ्यता, लोकज्ञान, संवेदना और सांस्कृतिक चेतना भारतीय भाषाओं में ही जीवित हैं। इसलिए न अंग्रेज़ी का विरोध समाधान है, न उसे स्वदेशी मानकर भारतीय भाषाओं का विकल्प बनाना। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है, जहाँ न्याय जनता की भाषा में मिले, शिक्षा मातृभाषा में विकसित हो, तकनीक हर भारतीय भाषा को समान अवसर दे और अंग्रेज़ी दुनिया से संवाद का सेतु बने, प्रभुत्व का नहीं। अंततः यह बहस अंग्रेज़ी की नहीं, भारत के भाषाई आत्मविश्वास की है। जो राष्ट्र अपनी भाषाओं को सम्मान देता है, वही अपने ज्ञान, संस्कृति और भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। भारत की वास्तविक भाषाई स्वतंत्रता अंग्रेज़ी को स्वदेशी सिद्ध करने में नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय जीवन का स्वाभाविक आधार बनाने में है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैयाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ब्रिटेन में 16-17 वर्ष के किशोरों के लिए स्वैच्छिक रात्रिकालीन सोशल मीडिया कर्फ्यू की योजना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

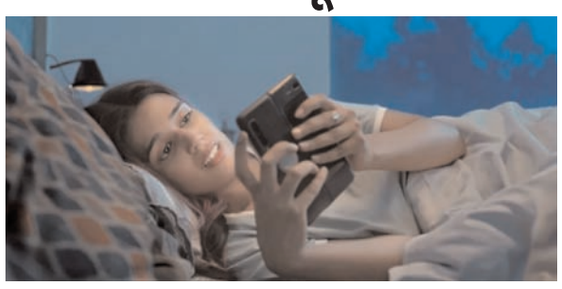

लंदन/एपी। ब्रिटिश सरकार ने 16 और 17 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के लिए रात के समय स्वैच्छिक सोशल मीडिया कर्फ्यू लागू करने की योजना की बुधवार को घोषणा की। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन होने के नुकसान से बचाना है। सरकार ने कहा कि लंबे समय तक उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन से जोड़े रखने वाली सुविधाएं, जैसे एक के बाद एक वीडियो अपने-आप चलने (ऑटोप्ले) का विकल्प, भी बड़े किशोरों के लिए अपने आप बंद रहेगा। हालांकि, आलोचकों ने इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि किशोर चाहें तो इन डिफॉल्ट सेटिंग' को स्वयं बदल सकेंगे।

यह प्रस्तावित प्रतिबंध सरकार द्वारा एक महीने पहले 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की योजना की घोषणा के बाद आया है। यह प्रतिबंध अगले वर्ष बसंत से स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे मंचों पर लागू होने की संभावना है, जबकि व्हाटसऐप और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाएं इसके दायरे से बाहर रहेंगी। प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में लाई गई इन योजनाओं को लागू करने के लिए कानून बनाना होगा। माना जा रहा है कि उनके संभावित उत्तराधिकारी एंडी बर्नहैम भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।

ब्रिटेन के ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री कनिष्क नारायण ने इस आशंका को खारिज किया कि किशोर स्वैच्छिक रूप से सोशल मीडिया कर्फ्यू को नजर अंदाज करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा मानना किशोरों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 300 से अधिक किशोरों और उनके अभिभावकों पर किए गए एक हालिया पायलट कार्यक्रम में रात के समय सोशल मीडिया के इस्तेमाल में उल्लेखनीय कमी आई। इसके साथ ही प्रतिभागियों की नींद और एकाग्रता में भी सुधार देखा गया।

उन्होंने 'स्काई न्यूज' से कहा, ''अक्टूबर में कुछ मंचों ने इस तरह की डिफॉल्ट सेटिंग लागू की थीं। 90 प्रतिशत से अधिक किशोरों ने हमें बताया कि उन्होंने इन सेटिंग को बरकरार रखा है। इसलिए उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट हैं और इस पहल का उद्देश्य भी स्पष्ट है।'' ब्रिटेन की प्रमुख बाल अधिकार संस्था 'एनएसपीसीसी' ने कहा कि ये प्रस्ताव युवाओं के सोशल मीडिया अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन अकेले ये पर्याप्त नहीं होंगे। इंग्लैंड की बाल आयुक्त रेचल डी सूजा ने इस पहल को ''सकारात्मक कदम'' बताया। उन्होंने कहा कि युवा सोशल मीडिया का उपयोग कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कठिनाई होती है। उन्होंने कहा, ''मैं यह जानना चाहती हूं कि कर्फ्यू जैसी नीतियों को किस तरह लागू किया जाएगा । मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इन पर करीबी नजर रखूंगी कि वे प्रभावी साबित हों।''

उच्चतम न्यायालय में अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार विधि छात्रों को जेल भेजा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दो विधि छात्रों को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों छात्रों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दिल्ली पुलिस का 14 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध स्वीकार करते हुए 24 वर्षीय प्रबल प्रताप और 23 वर्षीय चंदर भान को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि दोनों को 29 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

प्रबल प्रताप उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष का छात्र है। वह इस मामले में स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में अदालत में पेश हुआ था। वहीं, चंदर भान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का रहने वाला है और विधि पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष का छात्र है। दोनों को 10 जुलाई को हुई घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना उच्चतम न्यायालय में 'प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' से संबंधित विशेष अनुमति याचिका (सिविल) की सुनवाई के दौरान हुई थी। पुलिस के अनुसार, प्रबल प्रताप ने सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अदालत कक्ष के अंदर कागज फेंके और हंगामा किया, जिससे कार्यवाही बाधित हुई।

पुलिस के अनुसार, जब एक सुरक्षाकर्मी ने प्रबल प्रताप को रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें अपनी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने का प्रयास किया। इस मामले में तिलक मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जागरूकता

मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान की शुरुआत के लिए आयोजित एक नशा विरोधी जागरूकता रैली के दौरान प्रतिभागियों का नेतृत्व करता एक रोबोट।

रानी मुखर्जी को मिलेगी मानद डॉक्टरेट

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्रियों में शुमार रानी मुखर्जी ने अपने तीन दशक लंबे फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि समाज के कई अहम मुद्दों को भी उठाए। अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ला ट्रोब यूनिवर्सिटी उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित करेगी। यह सम्मान उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2026 के दौरान दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर रानी ने कहा कि सिनेमा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है और इसी ने उन्हें जीवन को अलग-अलग नजरिए से समझना सिखाया। रानी मुखर्जी ने इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सिनेमा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है।

मैंने हमेशा माना है कि अच्छी कहानियां लोगों के भीतर संवेदनाएं जगाने, जरूरी विषयों पर बातचीत शुरू करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखती हैं।'' रानी मुखर्जी को यह मानद उपाधि 14 अगस्त 2026 को मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा होगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे सामाजिक कार्यों को भी मान्यता देता है।

अपने सम्मान को लेकर रानी मुखर्जी ने कहा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न लंबे समय से दुनिया के सामने भारतीय सिनेमा की बेहतरीन तस्वीर पेश करता रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ला ट्रोब यूनिवर्सिटी और आईएफएफएम की पूरी टीम की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। यह मेरे लिए बेहद यादगार पल है। रानी ने अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए कहा, ''मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे ऐसे किरदार निभाने का अवसर मिला, जिनके जरिए मैं संघर्ष, हिम्मत, जुनून और उम्मीद जैसी भावनाओं को पर्दे पर दिखा सकीं। इंसानी कहानियां हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती रही हैं।

हर किरदार ने मुझे कुछ नया सिखाया। ऑस्ट्रेलिया और आईएफएफएम से मिला यह सम्मान मैं अपने देश भारत और दुनिया भर के उन सभी लोगों को समर्पित करती हूं, जिनके प्यार और भरोसे ने मुझे एक अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ने की ताकत दी। दर्शकों के प्यार ने ही मेरी जिंदगी को इतना समृद्ध बनाया है।''

जमीन विवाद को लेकर युवक पर हमले के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार

छतरपुर (मप्र)/भाषा। छतरपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी करने के आरोप में बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक दिन पहले मंगलवार को पुलिस ने गर्ग और उसके तीन साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राजनगर थाना क्षेत्र में हुई घटना में गर्ग और अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान अज्ञात आरोपियों के नाम जानने की कोशिश की जा रही है।

पटले ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और गाली-गलौच के आरोप में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद से जुड़ी घटना जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में मंगलवार दोपहर हुई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य एकत्र किए और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका शालिग्राम गर्ग से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि वह दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। हमले में घायल मोती कुशवाहा (30) को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि कुशवाहा अपने घर पर था, तभी गर्ग और उसके तीन साथियों ने उसे ललकारा और जब वह घर से बाहर आया तो आरोपियों ने उस पर लाठियों से हमला किया और कथित तौर पर गोलियां भी चलाईं।

पकुशवाहा ने पुलिस को बताया कि एक गोली उसके शरीर को छूते हुए निकल गई। पीड़ित का आरोप है कि वह जुगल किशोर पांडेय नामक व्यक्ति की ओर से गर्ग के खिलाफ जमीन पर कथित कब्जे से जुड़े मामले में गवाही देने वाला था।

सलमान खान की 'मातृभूमि' की राह हुई लंबी

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पहले इस फिल्म को अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की योजना थी, लेकिन अब इसके इस वर्ष रिलीज होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक, फिल्म से जुड़े कुछ लंबित मुद्दों के कारण इसकी रिलीज लगातार टल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म को रिलीज करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यदि मौजूदा समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसे वर्ष 2027 तक टाला जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यदि विवाद जल्द सुलझ भी जाता है, तब भी उपयुक्त रिलीज डेट मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश प्रमुख तारीखें पहले से बुक हैं। बताया गया है कि सलमान खान किसी अन्य बड़ी फिल्म से बॉक्स ऑफिस टकराव से बचना पसंद करते हैं और इसी वजह से जल्दबाजी में रिलीज का फैसला नहीं लिया जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यदि 'मातृभूमि' अगले साल तक टलती है तो 2027 में सलमान खान की दो बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती हैं। उनकी दूसरी फिल्म ' एसवीसी63', जिसमें अभिनेत्री नयनतारा भी नजर आएंगी, ईद 2027 के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित बताई जा रही है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बताया जा रहा है कि फिल्म की विषयवस्तु को लेकर उठी आपत्तियों के कारण इसे अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से अंतिम प्रमाणपत्र नहीं मिल पाया है। ऐसे में फिल्म की रिलीज पर अंतिम फैसला सेंसर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।

फिल्म 'जन नायकन' 23 को होगी रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। इसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। रिलीज डेट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच उत्साह साफ देखा जा सकता है। फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि 'जन नायकन' 23 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म विजय के अभिनय करियर को एक यादगार विदाई देगी। विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश-विदेश में भी है। यही वजह है कि 'जन नायकन' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है, जबकि इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म में दमदार कहानी, बड़े स्तर का निर्माण और शानदार सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा। पूरी टीम फिल्म को विजय के करियर के अनुरूप एक यादगार फिल्म बनाने में जुटी हुई है।

फिल्म निर्माता वेंकट के. नारायण ने रिलीज डेट की घोषणा के साथ खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा, सिनेमा में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और 'जन नायकन' भी उन्हीं खास पलों में से एक है। थलापति विजय के बड़े पर्दे पर आखिरी बार नजर आने वाली फिल्म का हिस्सा बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें खुशी है कि हम यह फिल्म दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसकों तक पहुंचा रहे हैं।

वेंकट के. नारायण ने आगे कहा, विजय का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने एक अभिनेता के रूप में करियर शुरू किया और मेहनत, लोकप्रियता और लोगों से जुड़े रहने के कारण लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। यही भरोसा और प्यार उन्हें राजनीति तक लेकर आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि जनता के साथ उनका रिश्ता कितना मजबूत है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि 'जन नायकन' दर्शकों के लिए एक यादगार सिनेमाई अनुभव साबित होगी। यह फिल्म विजय के शानदार फिल्मी करियर को एक भावनात्मक विदाई देगी, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

प्रचार

नई दिल्ली के 'द ललित' होटल में आगामी पंजाबी रोमांटिक फिल्म इश्कनामा के प्रचार कार्यक्रम के दौरान अभिनेता शहनाज़ गिल और जय रंधावा।

'उड़ता तीर' के सेट से सामने आया आयुष्मान-सारा का धमाकेदार डांस

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इस बीच फिल्म के सेट से एक बिहाइंड द सीन्स (बीटीएस) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों कलाकार रोमांटिक अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद फिल्म को लेकर प्रशंसकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। वायरल वीडियो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लोकप्रिय गीत 'ऐ काश के हम' की धुन पर रोमांटिक डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सारा सिल्वर रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं, जबकि आयुष्मान नीले रंग के सूट में दिखाई दे रहे हैं। इस क्लिप को देखने के बाद प्रशंसक यह कयास लगा रहे हैं कि क्या यह गीत फिल्म का हिस्सा होगा या सिर्फ शूटिंग का एक अभ्यास दृश्य है।

बताया जा रहा है कि 'उड़ता तीर' एक जासूसी कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें आयुष्मान एक बार फिर अपने चिर-परिचित हास्य अंदाज में दिखाई देंगे। इससे पहले आयुष्मान और सारा की जोड़ी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में नजर आई थी, जिसे दर्शकों ने पसंद किया था। अब दोनों दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।

हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक रिलीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन फिल्म ट्रेड विश्लेषक तरण आदर्श के अनुसार 'उड़ता तीर' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। यदि यह तारीख तय रहती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर सैफ अली खान और अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'हैवान' से होगी। ऐसे में पहली बार सारा अली खान और उनके पिता सैफ अली खान की फिल्में आमने-सामने नजर आ सकती हैं।

मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए : अंजना सुखानी

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी ने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जॉन अब्राहम और अजय देवगन जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। अब वह अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं। इस कड़ी में आईएएनएस के साथ बातचीत में अंजना ने फिल्म, इम्तियाज अली के साथ काम करने के अनुभव, फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव और अपने लंबे सफर को लेकर कई बातें साझा कीं। अंजना सुखानी ने कहा, ''मेरे लिए 'मैं वापस आऊंगा' बेहद खास फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म से इम्तियाज अली का नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। दुनियाभर के कलाकार उनके साथ काम करने का सपना देखते हैं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे यह मौका मिला। फिल्म की पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, खासकर नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ के साथ। नसीर साहब के साथ काम करना किसी लाइव मास्टरक्लास जैसा अनुभव है। उन्हें देखकर ही अभिनय की बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं।'' फिल्म में वेदांग रैना और शरवरी के साथ काम करने के अनुभव पर अंजना ने कहा, ''मेरी कहानी फिल्म में अलग समय से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके साथ ज्यादा सीन नहीं थे। हालांकि, ट्रेलर लॉन्च और शूटिंग के दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुईं। वेदांग और शरवरी दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं। जब मैंने दोनों का पहला सीन देखा तो मैं काफी प्रभावित हुई। वे फिल्म में नई ऊर्जा लेकर आए हैं।''

आज के समय में मॉडल, अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के बीच की दूरी कम हो रही है। इस बदलाव पर अंजना ने कहा कि अब चीजें काफी बदल गई हैं। पहले भी मॉडल फिल्मों में आते थे और अभिनेता मॉडलिंग करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी अभिनय की दुनिया में आ रहे हैं। किसी व्यक्ति में टैलेंट है और वह सच में अभिनेता बनना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। आखिर में सबसे जरूरी चीज यह है कि कलाकार अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित कर पाता है या नहीं।

मल्टीस्टारर फिल्मों के बढ़ते चलन पर अंजना ने कहा, ''सबसे जरूरी बात फिल्म की सफलता है। फिल्म छोटी हो या बड़ी और उसमें कितने कलाकार हों, इससे ज्यादा मायने रखता है कि दर्शक उसे पसंद करते हैं या नहीं। जब कोई फिल्म सफल होती है तो इसका फायदा सिर्फ कलाकारों को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिलता है। टेक्नीशियन, लाइटिंग टीम, स्पॉट बॉय और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों को काम मिलता है। मेरी दर्शकों से अपील है कि वे फिल्मों को थिएटर में जाकर जरूर देखें।'' अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने के अनुभव को याद करते हुए अंजना ने कहा, ''यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। करियर शुरू होने के कुछ सालों बाद मुझे अमिताभ बच्चन के साथ विज्ञापन करने का मौका मिला और बाद में राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'डिपार्टमेंट' में भी उनके साथ काम किया। अमिताभ बच्चन और इम्तियाज अली जैसे दिग्गजों के साथ काम करना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।'' हिंदी और साउथ सिनेमा के अंतर पर अंजना ने कहा कि दोनों जगहों की कहानी कहने का तरीका अलग है। हिंदी फिल्में अक्सर पूरे देश के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जबकि क्षेत्रीय सिनेमा अपनी भाषा और संस्कृति से ज्यादा जुड़ा होता है। भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और कलाकारों को अलग-अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिलना एक अच्छी बात है।

जीतो व जेपीएफ द्वारा 'जेपीएफ फेस्ट 2.0' में अनेक विषयों पर हुई सार्थक चर्चा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) और जीतो प्रोफेशनल फोरम(जेपीएफ) साउथ ने जेपीएफ फेस्ट 2.0' का आयोजन किया। ज्ञान, स्वास्थ्य, नेटवर्किंग और मनोरंजन का संगम प्रस्तुत करने वाले इस एक दिवसीय उत्सव में 2%0 सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर डॉ. नीतू जैन द्वारा 'बीमारी से स्वास्थ्य की ओर' विषय पर एक वेलनेस सत्र आयोजित किया गया, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यावहारिक उपाय साझा किए गए। प्रसिद्ध वक्ता निखिल शाह और डॉ. विश्व प्रमोद द्वारा वैश्विक परिदृश्य के बदलते स्वरूप और उसके व्यवसाय, अर्थव्यवस्था व समाज पर प्रभाव पर चर्चा की। नेहा बवेजा के मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट सत्र ने प्रतिभागियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में स्पष्टता, दृढ़ता और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 'उत्तराधिकार योजना' विषय पर पैनल चर्चा रही। इसमें ज़ील गाला, संजय सेठिया और नरेन्द्र जैन ने अपने विचार रखे। चर्चा का संचालन नितिन सुराना ने किया। इस अवसर पर साउथ के अध्यक्ष रणजीत सोलंकी, उपाध्यक्ष राजकुमार कोठारी एवं महेन्द्र रांका, मुख्य सचिव नितिन लुनिया सहित जेपीएफ संयोजक रौनक गुलेच्छा, जेपीएफ समिति के अध्यक्ष हरिकिशन छाजेड़, मुख्य सचिव प्रेक्षा भंडारी, संयुक्त सचिव अवनीप मेहता एवं कोषाध्यक्ष ऋषभ पिपाड़ा आदि उपस्थित थे।

एक अच्छे संकल्प के साथ माहेश्वरी महिला संगठन ने आयोजित किया संकल्प मेला

संभावित ग्राहकों ने मेले में जमकर की खरीददारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। माहेश्वरी सभा के माहेश्वरी महिला संगठन ने एक अच्छे उद्देश्य से एक दिवसीय 'महिला संकल्प मेले' का आयोजन किया। महिला सदस्याओं ने महिला सशक्तिकरण व मानवसेवा के संकल्प के साथ ओखलीपुरम स्थित माहेश्वरी भवन में बुधवार को खरीददारी प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें 80 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। इस संकल्प मेले में स्वर्णाभूषण व हीरे के आभूषण, साड़ी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, सौंदर्य प्रसाधन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बेडशीट, कृत्रिम गहने, घरेलू सजावट के सामान, राखी, कांच के सामान, गिफ्ट आइटम से लेकर खाने पीने के अनेक स्टॉल लगाए गए।

सुबह से ही प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में खरीददारों की भीड़ देखी गई और दोपहर को इस संख्या में इजाफा होता गया। इस एक दिवसीय संकल्प मेले में संभावित ग्राहकों विशेषकर महिला व युवतियों ने जमकर खरीददारी की। माहेश्वरी भवन के दो फ्लोर के चार हॉल में सभी स्टॉल लगाए गए। मेले में जयनगर के रायसोनी डायमंड ज्वेलर्स के मालिक रतनचंद बागरेचा द्वारा प्रदर्शित हीरों को महिलाओं ने पसंद दिया।

इस मेले में बेंगलूरु सहित बीकानेर व अन्य शहरों से भी आई महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मेले में महिला उद्यमियों ने राजस्थानी, गुजराती व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए जो आकर्षण का केन्द्र बने।

आने वाले त्यौहारों से पहले आयोजित इस मेले का उद्घाटन माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भगवानदास लाहोटी, कर्नाटक गोवा प्रांतीय महिला संगठन की अध्यक्ष सुनीता लाहोटी, महिला संगठन की अध्यक्ष विजयलक्ष्मी सारड़ा, सचिव शोभा भूतड़ा, माहेश्वरी कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डागा आदि ने भगवान महेश के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी सारड़ा ने सभी दुकानदारों का स्वागत किया तथा मंत्री शोभा भूतड़ा ने बताया कि मेले से बचत धनराशि का जनसेवार्थ के कार्यो के लिए उपयोग में किया जाएगा ।

जीतो नॉर्थ लेडीज़ विंग ने आयोजित किया अनवीलिंग यू-शी'ज़ दि सॉल्यूशन' कार्यक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन(जीतो) नॉर्थ लेडीज़ विंग ने 'अनवीलिंग यू-शी'ज़ दि सॉल्यूशन' विषय पर नए कार्यालय में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया जिसमें 125 सदस्याओं ने भाग लिया। नॉर्थ के अध्यक्ष विमल कटारिया ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका केवल प्रेरणादायक ही नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी भी है। नेमीचंद जैन ने लेडीज़ विंग की सराहना की। लेडीज़ विंग की अध्यक्ष लक्ष्मी बाफना ने सभी का स्वागत किया। मुख्य सचिव रक्षा छाजेड़ ने कार्यक्रम की जानकारी दी।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रेया घोड़ावत ने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि जागरूकता और संवेदनशीलता किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। कार्यक्रम में अहिंसा, नैतिक जीवनशैली, सतत विकास, सजग उपभोग, वेगन फूड तथा भोजन, फैशन, स्किनकेयर और फुटवियर में उपलब्ध क्रूरता-मुक्त विकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर नॉर्थ के उपाध्यक्ष कमल पुनमिया, दिनेश बाफना सहित लेडीज विंग व युवा विंग के सदस्य उपस्थित थे। रक्षा छाजेड़ ने धन्यवाद दिया।

दूसरों की सहायता करना ही है जैन समाज का मूल सिद्धांत : साध्वीश्री संस्कारनिधि

नवनिर्मित भगवान महावीर जैन अस्पताल में हुई वास्तु पूजा, शांति पाठ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। शहर के जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में तथा साध्वी संस्कार निधिश्री आदि की निश्रा में सरदार वल्लभभाई पटेल नगर स्थित नवनिर्मित भगवान महावीर जैन अस्पताल में वास्तु पूजा, शांति पाठ हुआ तथा प्रभु महावीर स्वामी की प्रतिमा का विधिवत प्रवेश कराया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कांतिलाल चौहान ने बताया कि इस अस्पताल में शारीरिक स्वास्थ्य जांच के तहत रक्तचाप, शुगर, दंत जांच, घुटना की जांच तथा रक्त जांच आदि की जांच की जाएगी।सुमतिनाथ महिला की ओर से स्नात्र सहित सभी प्रकार की पूजा पढ़ाई गई। साध्वीश्री की निश्रा में अस्पताल निर्माण के लाभार्थी चंपाबाई-गुलाबचंद राठौड़ परिवार, अनुष्ठान के लाभार्थी वसंत कुमार, सुंदरबाई परिवार का ट्रस्ट की ओर से सम्मान किया गया। साध्वीश्री ने लाभार्थियों व ट्रस्टियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी उपस्थित लोग समाजसेवा के तहत महावीर स्वामी के नाम को निरंतर आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जैन समाज की समाजसेवा का मूल आधार 'परस्परोपग्रहो जीवनाम अर्थात सभी जीव एक-दूसरे की सहायता करें' का सिद्धांत है। जैन समुदाय मुख्य रूप से अहिंसा, अपरिग्रह और जीव दया के सिद्धांतों का पालन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में अग्रणी योगदान देता रहा है। जैन समाज शिक्षा के क्षेत्र का प्रसार कर जैन विद्यालय का निर्माण करवाता है ताकि ज्ञान प्रदान कर सच्ची सेवा की जा सके। देशभर में ऐसे कई शहर-गाँव मिलेंगे जहाँ जैन ट्रस्टों द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गुरुकुल मौजूद हैं। ये संस्थान बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को आधुनिक और नैतिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ और औषधालय स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैन समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, मैसूरु के अध्यक्ष कांतिलाल चौहान, उपाध्यक्ष वसंत राठौड़, सचिव प्रवीण दांतेवाड़िया, सहसचिव घेवरचंद जैन, कोषाध्यक्ष पारस जैन, अशोक दांतेवाड़िया, हंसराज पगारिया, गौतम सालेचा, हीराचंद कांगटानी सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

आमंत्रण

बेंगलूरु के कर्नाटक इनरवियर एसोसिएशन(किया) बेंगलूरु के अध्यक्ष महावीरचन्द मेहता व उपाध्यक्ष अश्विन सेमलानी ने बेंगलूरु प्रवास पर आए हुब्बली के समाजसेवी महेन्द्र सिंघी से मुलाकात कर उन्हें कर्नाटक इनरवियर ट्रेड फेयर में अतिथि के रूप में शामिल होने का निवेदन किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश चोपड़ा, संयुक्त कोषाध्यक्ष विनोद चौहान सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

कलबुर्गी में पुलिस पर हमला करने वाले फरार कैदी के पैर में लगी गोली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कलबुर्गी/भाषा। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक फरार कैदी ने बुधवार को उसे पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला कर दिया हालांकि जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने यह जानकारी दी। कर्नाटक सरकार ने जेल से फरार होने की घटना के बाद लापरवाही के आरोप में संबंधित जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी संतोष ने पुलिसकर्मियों पर उस समय कथित रूप से हमला किया, जब पुलिस ने उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे संतोष के पैर में गोली लगी। इस घटना में दो पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, संतोष समेत तीन कैदी मंगलवार तड़के यहां कलबुर्गी केंद्रीय कारागार के स्नानगृह की ग्रिल कथित रूप से काटकर और सीढ़ी की मदद से फरार हो गए थे। बाकी दो दोषी कैदियों का पता लगाने के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संतोष और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए कलबुर्गी के सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने एक बयान में कहा कि कलबुर्गी केंद्रीय कारागार से तीन कैदियों के फरार होने के मामले में लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में संबंधित जेल अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एक कैदी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मंत्री ने बयान में कहा, गृह मंत्री का पद संभालने के बाद से मैंने गृह विभाग के हर प्रभाग की समीक्षा बैठक की है और सभी प्रभागों को मजबूत बनाने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं राज्य की सभी जेलों का निरीक्षण करूंगा और जेल कर्मचारियों की कार्यकुशलता की भी समीक्षा करूंगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जेल सुधार, सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ आलोचना करने के लिए मुंह खोले बैठे भाजपा नेताओं को चाहिए कि वे एक बार यह भी सोचें कि उनके शासनकाल में राज्य की जेलों की क्या स्थिति थी। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2010 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कोप्पल जिला जेल से आठ कैदी फरार हो गए थे। मंत्री ने पूछा, इसे राज्य के इतिहास की ऐसी सबसे बड़ी घटना माना जा सकता है। क्या भाजपा इसे उस समय के गृह मंत्री की विफलता मानेगी?

टीचर की पिटाई के बाद छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु । बेंगलुरु के मारियप्पनपाल्या इलाके के एक स्कूल में आठवीं कक्षा का एक छात्र अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आरोप है कि स्कूल स्टाफ द्वारा शारीरिक सजा और भेदभाव किए जाने के बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। मंगलवार को सामने आई इस घटना से छात्र के परिवार में भारी आक्रोश है। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट और संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। माता-पिता के अनुसार, 'राइट टू एजुकेशन' (आरटीई) कोटे के तहत पढ़ने वाले इस लड़के का स्कूल में अपने दो सहपाठियों के साथ झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि मामला हेडमास्टर तक पहुंचा, जिसके बाद शिक्षकों ने कथित तौर पर छात्र की पिटाई कर दी।

परिवार का आरोप है कि लड़के के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए थे और उसे दिन भर स्कूल परिसर में घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट पर यह आरोप भी लगाया है कि आरटीई कोटे के तहत एडमिशन होने की वजह से उसके साथ भेदभाव किया गया। कथित अपमान और शारीरिक हमले को बर्दाश्त न कर पाने के कारण छात्र बहुत परेशान हालत में घर लौटा। उसके पिता किराने की दुकान पर काम करते हैं, जबकि उसकी मां एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है।

घटना के समय घर पर कोई नहीं था, इसलिए लड़के ने कथित तौर पर अपनी चचेरी बहन को घटना के बारे में बताया और फिर छत के पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की।

कुछ गड़बड़ महसूस होने पर चचेरी बहन ने उसे देखा और पाया कि वह संघर्ष कर रहा था। उसने तुरंत उसे बचाया और परिवार के सदस्यों को सूचित किया।

छात्र को नयांडाहल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उसकी गंभीर चोटों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी में आई चोट भी शामिल है। परेशान माता-पिता ने अधिकारियों से तुरंत दखल देने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन पर शारीरिक दंड और भेदभाव के आरोपों की पुष्टि के लिए आगे की जांच चल रही है।

शहर में राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का किया सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेंगलूरु आगमन पर फार्मा कम्पनी के राजसंस समूह के कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर गोडवाड़ परगना के प्रमुख वरकाणा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ पेढ़ी के अध्यक्ष रमेश कुमार कोठारी के मैसूर रोड़ स्थित कार्यालय पहुंचने पर राठौड़ का सम्मान किया।

राठौड़ ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोठारी ने अपने पैतृक गांव बिठुडा पिरान में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है जो कि अनुमोदनीय है। इस अवसर पर सुराणा संघ बेंगलूरु कर्नाटक के अध्यक्ष महीपाल सुराणा, गुरु ज्येष्ठ पुष्कर भवन ट्रस्ट के महामंत्री महावीर मेहता आदि उपस्थित थे।

'कर्म के लिए निमित्त और उपादान दोनों सहयोगी'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के शूले स्थित केवलमुनि जैनोदय ट्रस्ट भवन में जयगच्छीय जैनाचार्यश्री पार्श्वचन्द्रजी व डां पदमचंद्रजी के सान्निध्य में पुरंदरमुनिजी ने प्रवचन में कहा कि कोई भी कर्म उदय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि का निमित्त कारण भूत हो सकता है।धुरंधरमुनिजी ने आर्त अशुभ ध्यान के चार कारणों की व्याख्या करते हुए कहा कि संसारिक जीव संयोग और वियोग के कारण दुखी होता है। वह प्रिय वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों का हमेशा संयोग चाहता है और अप्रिय चीजों का वियोग। जब इन वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का वियोग होता है तब मोहवश अशुभ ध्यान यानी आर्त ध्यान करता है।कार्यक्रम का संचालन शूले संघ के महामंत्री सुनील कुमार मरलेचा ने किया ।

महावीर धार्मिक पाठशाला का रजत जयंती उत्सव 19 को

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के महावीर जैन पाठशाला राजाजीनगर के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 19 जुलाई को सुबह मागड़ी रोड स्थित पुष्कर भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पाठशाला की प्रशिक्षिकाएं, ज्ञानार्थी, जिनेश्वर युवा मण्डल व ब्राह्मी कन्या मंडल के सदस्य विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पाठशाला संयोजक सुमतमल सुराणा ने बताया कि गौतमचन्द कमलचन्द भण्डारी परिवार के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ राजाजीनगर के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होंगे।

फीफा विश्व कप

स्पेन के मैड्रिड में फ्रांस और स्पेन के बीच फीफा विश्व कप सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए स्पेन टीम के प्रशंसक।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**